प्रत्येक सोमवार को हल्द्वानी से प्रकाशित

डाक पंजीयन संख्या यूए/नैनीताल-335/2017-2019

R.N.I No. - UTTHIN/2017/73662

कुमाऊं जनसंदेश

www.kumaonjansandesh.com

वर्ष–2 अंक–38 हल्द्वानी (नैनीताल) सोमवार 4 मार्च से 10 मार्च 2019 पृष्ठ–8 मूल्य 2 रुपये

पहाड़ी पिसी नूण की धमक दूर तलक

समूह व संस्थाओं ने पहाड़ी पिसी नूण को बनाया स्वरोजगार का जरिया

कुमाऊं जनसंदेश डेस्क

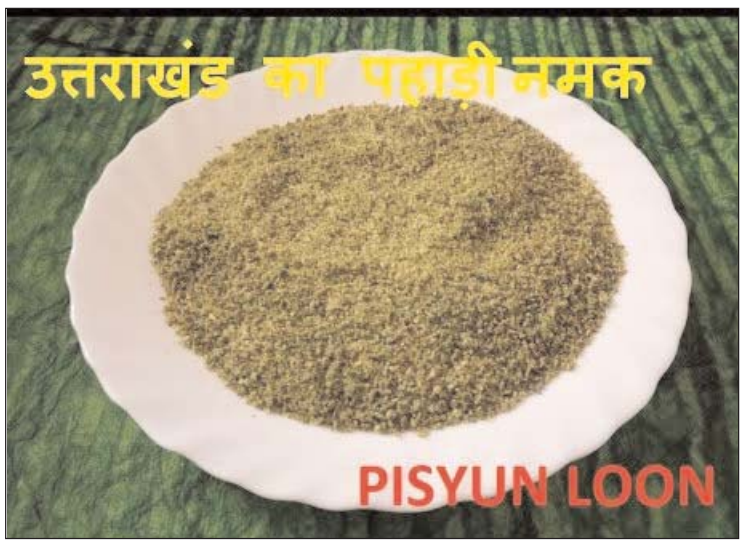

हल्द्वानी। पिछले दिनों हल्द्वानी में लगे सरस मेले के दौरान गुजरात के वडोदरा से आया एक दंपति वहां लगे स्टाल्स पर एक खास ब्रांड के पहाड़ी पिसी नूण को तलाश रहा था। पूछने पर उसने बताया कि वहां उसके पड़ोस में रहने वाले एक उत्तराखंड निवासी ने उसे हल्द्वानी से ले जाकर पहाड़ी पिसी नूण खिलाया था। उन्हें यह नमक इतना अच्छा और चटखारेदार लगा कि अब वे इसे ज्यादा मात्रा में ले जाकर अपने दूसरे दोस्तों को भी खिलाना चाहते हैं। गुजराती दंपति की रुचि यह बताने के लिए काफी है कि पहाड़ी पिसी नूण की धमक अब दूर तलक हो चली है।

दरअसल पहाड़ के इस परंपरागत स्वाद वाले पिसी नूण ने पिछले कुछ वर्षों में एक कारोबार का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। कुमाऊं मंडल में हल्द्वानी, कोटाबाग, काकड़ी घाट और पिथौरागढ़ और गढ़वाल मंडल में पौड़ी, कर्णप्रयाग आदि कई स्थानों पर अनेक समूह व संस्थाएं पहाड़ी पिसी नूण के कारोबार में लगे हैं। बढ़ते शहरीकरण और व्यस्त होती जिंदगी के बावजूद परंपरागत घरेलू स्वाद की चाह के कारण इन समूहों को अपने पिसी नूण के लिए ग्राहक भी आसानी से मिल रहे हैं।

पहले-पहल इस नूण की बिक्री कुछ मेलों में लगने वाले स्टालों और ग्राम्य विकास विभाग के हिमान्या मार्ट तक सीमित थी, लेकिन काकड़ी घाट के हिमालयन फ्लेवर ने सबसे पहले वहां एक दुकान खोलकर यह बताया कि पहाड़ी पिसी नूण पूरी तरह एक कारोबार भी हो सकता है। हिमालयन फ्लेवर ने इस कारोबार को एक दुकान तक सीमित रखा, लेकिन हल्द्वानी के ब्रांड बूढ़ी आमा ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए इसे संगठित कारोबार का रूप दे दिया और बड़ी कंपनियों के उत्पाद की तरह इस नूण और रेडीमेड भांग चटनी को दुकान-दुकान पहुंचाना शुरू किया। नतीजतन यह नूण अधिकाधिक ग्राहकों की पहुंच तक होने लगा।

आज स्थिति यह है कि पहाड़ी पिसी नूण का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। हल्द्वानी की अधिकांश दुकानों में यह अब दूसरे उत्पादों की तरह खूब बिकने लगा है। जिसे न केवल स्थानीय लोग खरीद रहे हैं, बल्कि देश के दूसरे प्रांतों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडी भी खरीदकर ले जा रहे हैं और गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबियों आदि को पिसी नूण का मुरीद बना रहे हैं। यही नहीं विदेश में रहने वाले भी यहां से अपने काम पर विदेश लौटते वक्त इसे उत्तराखंड की सौगात के तौर पर ले जाना नहीं भूलते।

पहाड़ी पिसी नूण का कारोबार कितना बड़ा होता जा रहा है, इसे लेकर बूढ़ी आमा ब्रांड की संचालिका श्रीमती उषा बताती हैं कि छह माह पहले जहां वे प्रति माह सिर्फ आठ-दस हजार का नूण बेच रहे थे, वहीं आज सिर्फ हल्द्वानी में ही उनका सत्तर से अस्सी हजार का नूण व भांग की चटनी बिक रहे हैं, जो क्रमोतर बढ़ोतरी की ओर है।

कुमाऊं कमिश्नर रौतेला ने कसे अफसरों के पेंच

काम में लापरवाही पर 17 अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण

हल्द्वानी। विभिन्न सेक्टरों केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा कुमाऊं मण्डल को 293075 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। ऐसे में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। यह बात आयुक्त कुमाऊँ मण्डल एवं सचिव मुख्यमंत्री राजीव रौतेला में तहसील कार्यालय में वीसी के माध्यम से मण्डल में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए दिए। उन्होंने जिला योजनाए राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित योजनाओं व बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति एवं व्यय की समीक्षा भी की। उन्होंने जनपद एवं विभागवार समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष में सभी योजनाओं में प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करते हुए शत प्रतिशत व्यय करने के निर्देश सभी विभागों के अधिकारियों को दिए।

रौतेला ने मण्डल के सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि साहूकारों की भाँति पैसा अपने पास न रखें तथा धनराशि का सदुपयोग करते हुए विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रतिदिन के अनुसार कार्य योजना तैयार करते हुए दिन-प्रतिदिन के अनुसार कार्य करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यों को मूर्त रूप देने के निर्देश दिये। उन्होंने कोषागारों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बिलों को लम्बित न रखने तथा तत्परता से बिल भुगतान की कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश देते हुए कहा कि मण्डल के विकास कार्य कोषागार की वजह से बाधित नहीं होने चाहिए। रौतेला ने सम्पादित हो चुके कार्यों के बिल प्राथमिकता से ट्रेजरी में लगाने के निर्देश सभी विभागों के अधिकारियों को दिये। रौतेला ने समाज कल्याण व महिला कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मण्डल के सभी विभागीय अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत दी जाने वाली समस्त पेंशन धारकों की चौथी किश्त की धनराशि में अविलम्ब रूप से एक मार्च को जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने समाज कल्याण तथा महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रकार के पेंशन धारकों के खातों में एक मार्च को चौथी किश्त की धनराशि अवश्य पहुंच जानी चाहिए।

उन्होंने समीक्षा के दौरान विभागीय पोर्टल के कारण छात्रवृत्ति वितरण में हो रही देरी पर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को पोर्टल से सम्बन्धित सभी समस्याएं चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संयुक्त निदेशक समाज कल्याण को एक सप्ताह के भीतर विभाग की आईटी सैल तथा सभी समाज कल्याण अधिकारियों के साथक बैठक या वीसी कराने के निर्देश दिये। संयुक्त निदेशक समाज कल्याण द्वारा कुछ जिलों के समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आईएफएससी कोड गलत उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई जिस पर आयुक्त ने गंभीर रूख अपनाते हुए सभी सीडीओ को आईएफएससी कोड के विषय में जॉच करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिये।

रौतेला ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी मदों में ए श्रेणी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कुमाऊं मण्डल के डी श्रेणी में चल रहे विभागों के 17 अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिये। उन्होंने पीएमजीएसवाई की चम्पावत डिवीजन के लिए स्थानान्तरित अधिशासी अभियन्ता योगेश पाल सिंह द्वारा अभी तक ज्वाइन न किये जाने को गंभीरता से लेते हुए अधिशासी अभिन्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई में अमल में लाने के निर्देश दिये। उन्होंने सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अल्मोड़ा जिले में तैनात सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता विनोद कुमार को योजनाओं का परीक्षण किये बिना ही जिला योजना में प्रस्तुत करने पर कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों व मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अधिकारियों की तीन दिन से अधिक समय की छुट्टी स्वीकृत करने पर मण्डलायुक्त को अवश्य अवगत कराया जाए तथा मण्डलायुक्त के संज्ञान में लाए बिना तीन दिन से अधिक की छुट्टी स्वीकृत न की जाए।

वीसी के दौरान रौतेला ने बताया कि आपदा एवं पुनर्वास के सम्बन्ध में उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, इस लिए सभी जिलाधिकारी अपने.अपने सुझाव उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में वृहद्ध बैठक आयोजित की जायेगी ताकि शासन को दूरदर्शी कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत की जा सके। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत पात्र किसानों को योजना से आच्छादित करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी व अपर जिलाधिकारियों को योजना की प्रगति की निगरानी करने के लिए नामित करने के निर्देश देते हुए योजना की प्रगति का प्रतिदिन डाटा संग्रण करने के निर्देश दिये। ज्ञात हो कि शासन स्तर से मण्डल को जिला योजना में 22492 लाख रुपये की धनराशि का 71 प्रतिशत, राज्य सेक्टर में 141049 लाख रुपये की धनराशि का 77 प्रतिशत तथा केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत 115268 लाख रुपये की धनराशि का 81 प्रतिशत, बाह्य सहायतित योजना में 14266 का 91 प्रतिशत सम्बन्धित विभागों द्वारा व्यय किया जा चुका है।

इस प्रकार मण्डल को अवमुक्त 293075 लाख की धनराशि के सापेक्ष 230609 का व्यय हो चुका है जोकि कुल धनराशि का 79 प्रतिशत है। वीसी में जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन, मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार, विद्युत विभाग के मुख्य अभियन्ता एचके गुरुरानी, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या राजेन्द्र तिवारी, जिला अर्थ एवं सांख्याधिकारी एलएम जोशी, मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार के अलावा सभी जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की समुचित व्यवस्था बहुत जरुरी : दरम्वाल

ब्लाक सभागार में क्षमता विकास अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला में वक्ताओं ने रखे विचार

हल्द्वानी। विकासखण्ड कार्यालय सभागार में ब्लॉक प्रमुख आनन्द सिंह दरम्वाल की अध्यक्षता में ो ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अधिप्राप्ति नियमावली विषय पर एक दिवसीय क्षमता विकास अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा तरक्की की राह पर ष्मेरा गॉव रथ को झण्डी दिखाकर विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों में योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख दरम्वाल ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतें स्वच्छ एवं सुन्दर भविष्य के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं निस्तारण के क्षेत्र में प्रभावशाली कदम उठाऐं ताकि भविष्य में ग्राम पंचायतों को ठोस अपशिष्ट के कारण दूषित न होना पड़े। उन्होंने ग्राम प्रधानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में समय रहते ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यवस्था न होने के कारण अपशिष्ट के अव्यवस्थित तरीके से बिखरे होने के कारण पर्यावरण दूषित होता है जोकि आसपास के परिवेश को प्रभावित करता है। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों को अपने.अपने क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों एवं अपशिष्ट की प्रकृति के अनुसार कार्य योजनाएं तैयार करने को कहा।

इस अवसर पर खण्ड विकास अधिकारी एचएस मेहरा तथा एडीपीआरओ दिनेश चन्द्र जोशी ने कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पंचायतों में ठोस अपशिष्ट का समुचित प्रबन्धन, पंचायतों की सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ-साथ गुणवत्ता बनाए रखना कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों से कार्यशाला में दिए जा रहे प्रशिक्षण का लाभ जनता तक पहुँचाने का आह्वान किया। कार्यशाला में पर्यावरणीय शिक्षण एवं ग्राम विकास समिति की प्रशिक्षिकाओं अनुराधा जोशी, पुष्पा काण्डपाल तथा डॉ.मनीषा द्विवेदी ने ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति एवं उसके क्रियान्वयन, पीईएस एप्लीकेशन की जानकारी एवं क्रियान्वयन, अधिप्राप्ति नियमावली की जानकारी, ऑडिट एवं परिपालन की प्रक्रिया, जीपीडीपी, महिला विकास एवं पंचायतें, एमआईएस डैशबोर्ड का महत्व एवं आवश्यकता आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में ग्राम प्रधान रेखा जग्गी, मुन्नी देवी, भगवती बिष्ट, बालादत्त खोलिया, इन्दु काण्डपाल, दिनेश चन्द्र आर्य, विरेन्द्र सिंह बिष्ट, एडीओ बसंत सिंह मेहता, प्रकाश काण्डपाल, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी शाहनवाज, रूहीनाज, विपिन कुमार, हरीश लाल, ललित ग्वाल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन धीरेन्द्र कुमार पन्त ने किया।

स्वरोजगार के लिए उठाएं एससी-एसटी हब योजना का लाभः मेयर

बैठक में एससी-एसटी उद्यमियों को किया गया प्रोत्साहित

हल्द्वानी। नगर निगम मेयर डा. जोगेंद्र रौतेला ने कहा कि सरकार ने लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए तमाम योजनाएं संचालित की हैं। इनमें से ऐसी ही एक अच्छी योजना है एससी-एसटी हब योजना। लोगों को चाहिए कि वे विभाग से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बन जाएं।

बीते म गलवार को अनुसूचित जाति-जनजाति हब योजना के प्रचार प्रसार के लिए मुखानी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एससी-एसटी उद्यमियों को योजना की विस्तार से जानकारी दी गई और योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया गया। ब्लॉक प्रमुख आनंद सिंह दरम्वाल ने भी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक योगेश चंद्र पांडे ने कहा कि एससी-एसटी योजना के तहत एससी-एसटी उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों को सरकारी खरीद में चार प्रतिशत की वरीयता दिये जाने का प्रावधान है। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

योजना में एससी-एसटी उद्यमियों, भावी उद्यमियों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें कौशल विकास करना, एमएसएमई, डीआईसी व उद्योग संघों के माध्यम से वेंडर विकास कार्यक्रम कर राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मेला-प्रदर्शनियों में उद्यमियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के अलावा विपणन एवं उत्पाद की गुणवत्ता के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित एवं लाभांवित करना है। सहायक प्रबंधक ओपी भटट ने पीएमईजीपी सहित अन्य विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।

डिजायन विशेषज्ञ रवि शेखर ने उत्पाद में डिजायन की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस मौके पर खादी कमीशन के केसी कांडपाल, संस्था के संस्थापक महेश भटट, प्रेमा रत्नाकर सहित तमाम उद्यमी मौजूद थे।

खाद्य प्रसंस्करण को लेकर नगर निगम में एमएसएमई कार्यशाला आयोजित

हल्द्वानी। मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि यह अच्छी बात है कि युवा अब सिर्फ स्वरोज़गार के लिए आगे ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि स्वरोजगार स्थापित कर दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं।

उन्होंने नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्योग लगाने के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने का प्रयास करें। कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प है। सीडीओ विनीत कुमार को एक जिला एक उत्पाद के तहत नगर निगम सभागार में आयोजित एमएसएमई कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभागीय अनुदान परक योजनाओं का लाभ उठाने के साथ ही प्रशिक्षण भी प्राप्त करें जिससे कि उद्यमियों को उद्यमी स्थापित करने में आसानी हो सके।

कार्यशाला में मुख्य उद्यान अधिकारी भावना जोशी ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के फायदे, विभागीय योजनाओं और अनुदान के बारे में जानकारी दी। जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक योगेश चंद्र पांडे ने पीएमईजीपी, एससीएसटी हब योजना सहित उद्योग विभाग के अंतर्गत संचालित अन्य रोजगारपरक योजनाओं की जानकारी दी। एसोचेम के अधिकारी श्रीश कुमार कौशिक ने एसोचेम के बारे में विस्तार से बताया। सहायक आयुक्त राज्य कर विनय कुमार ओझा ने जीएसटी से जुड़ी जिज्ञासाओं व शंकाओं का समाधान किया। लीड बैंक अधिकारी एमएस जंगपांगी ने बैंकिंग व लोन के बारे में बताया। इसके अलावा बागवानी बोर्ड, बागवानी मिशन, एमएसएमई नीति-2015, मुद्रा योजना, स्टार्ट अप, स्टैंड अप आदि योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर कर्मचारी बीमा निगम के ललित शर्मा, डा. राहुल मेर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

हेमंत बने जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री

हल्द्वानी। शहर के सक्रिय व युवा हेमन्त साहू को जिला कांग्रेस कमेटी ने स्थान दिया है। उन्हें जिला कांगे. स कमेटी का महामंत्री बनाया गया है। बता दें कि हेमंत साहू लम्बे समय से समाजसेवा में जुटे हुए हैं और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जनमुद्दों को उठाते रहते हैं। उनकी सक्रियता व निष्ठा को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री पद दिया गया है। साहम ने कमेटी को भरोसा दिलाया है कि वे जिला नेतृत्व की उम्मीदों में खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और दोगुने जोश से पार्टी हित में कार्य करेंगे। साहू ने मनोनयन पर नेता प्रतिपक्ष इन्दिरा हृदयेश, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह व जिला अध्यक्ष सतीश नैनवाल, मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष सुमित हृदयेश का आभार व्यक्त किया है।

कमिश्नर ने किया कटारमल सूर्य मन्दिर का भ्रमण

अल्मोड़ा। आयुक्त व सचिव मुख्यमंत्री राजीव रौतेला ने बीते शुक्रवार को कटारमल स्थित सूर्य मन्दिर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कटारमल के आसपास स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था केएमवीएन के अधिकारियों से कहा कि जो भी कार्य किये जा रहे हैं उन्हें तय समय में पूर्ण करें। साथ ही गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान दिया जाए। सचिव ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के उददेश्य से भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्वदेश दर्शन के अन्तर्गत जो भी निर्माण कराये जा रहे हैं उन्हें केएमवीएन स्वयं मानिटरिंग करें। इस दौरान उन्होंने बनाये गये रास्ते व निर्माणाधीन गेस्ट हाउस आदि का भी निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की 13 डिस्ट्रिक 13 डेस्टीनेशन के अन्तर्गत भी कटारमल व स्याहीदेवी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करवाये जा रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित लोगों की भी समस्या सचिव द्वारा सुनी गयी। ग्रामीणों ने बताया कि कटारमल में पानी की बहुत समस्या है जिस पर उन्होंने मुख्य अभियन्ता पेयजल निगम के साथ बैठकर ठोस हल निकालने का आश्वासन दिया साथ ही केएमवीएन द्वारा सोलर पावर बनाये जाने की योजना है जिससे ग्रामवासियों की पेयजल की किल्लत कम हो सकेगी। सचिव द्वारा इस अवसर पर विभिन्न कार्यों की प्रगति भी जानी। उन्होंने कहा कि कटारमल को पर्यटन हब बनाने के प्रयास जारी हैं। इससे पूर्व सचिव ने कटारमल मन्दिर में पूजा-अर्चना भी की। इस अवसर पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि उनके द्वारा भी समय-समय पर यहाँ आकर प्रगति के बारे में केएमवीएन से विचार-विमर्श किया जाता है।

कुमाऊं जनसंदेश पब्लिकेशन

कुमाऊं जनसंदेश - हिंदी समाचार पोर्टल

कुमाऊं जनसंदेश - साप्ताहिक समाचार पत्र

फ्लेक्स, होर्डिंग्स, बैनर

सभी तरह का प्रिंटिंग जॉब वर्क

Website- www.kumaonjansandesh.com

Email- vinodpaneru123@gmail.com

Mo.- 9410354318, 9012515795

किसान सम्मान निधि योजना को किसानों ने बताया संजीवनी

प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर से योजना को किया लांच

हल्द्वानी। सीमान्त और छोटे किसानों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में किया। मोदी ने किसानों के हित की इस योजना की लॉचिंग की तथा देशभर के विभिन्न प्रान्तों के चयनित किसानों से दो तरफा संवाद कायम करते हुए वार्ता भी की। वार्ता के दौरान लघु एवं सीमान्त किसानों ने इस योजना को संजीवनी बताया। इस योजना का वेब कास्टिंग के माध्यम से सीधा प्रसारण देशभर के विकासखण्डों में भी किया गया। जिला का मुख्य कार्यकम विकास खण्ड हल्द्वानी सभागार में आयोजित किया गया,जिसके मुख्य अतिथि विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत थे। अपने सम्बोधन में किसानों को सम्बोधित करते हुए भगत ने कहा कि छोटे किसानों को मिलने वाली इस आर्थिक मदद से उन्हें बीज, खाद, सिंचाई, उर्वरक एवं कृषि रसायन जैसे संसाधनों को जुटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस मदद से किसानों को ऊँची दरों के ब्याज पर साहूकारों से पैसा नहीं उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दो गुनी हो, इसके लिए प्रदेश स्तर पर भी कार्यवाही गतिमान है।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि जनपद में 42600 लघु एवं सीमान्त किसान हैं जिनमें से 37500 पात्र किसानों के फार्म भरवा दिए गए है तथा 24 हजार किसानों का डाटा सम्बन्धित साइट पर अपलोड भी कर दिया गया है तथा शेष डाटा माह के अन्त तक अपलोड कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पात्र किसानों के फार्म भरवाने की प्रक्रिया भी जारी है।

इससे पूर्व मनकी बात कार्यक्रम का भी सीधा प्रसारण किसानों एवं जनता को दिखाया गया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य प्रकाश गर्जोला, लाखन निगलटिया, पार्षद प्रमोद पन्त के अलावा नरेन्द्र सिंह मेहरा, संयुक्त निदेशक कृषि पीके सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार, खण्ड विकास अधिकारी हरीश मेहरा सहित दर्जनों किसान मौजूद थे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरु

रुद्रपुर। जनपद के लघु एवं सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम-किसान योजना का शुभारंभ एपीजे अब्दुल कलाम कलक्टेट सभागार में स्थानीय विधायक राजकुमार ठुकराल, मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, अपर जिलाधिकारी नजूल जगदीश चन्द्र काण्डपाल एवं जिला कृषि अधिकारी अभय कुमार सक्सेना ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर विधायक को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। विधायक द्वारा जिले के लघु एवं सीमान्त किसानों को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आंचलों में विषम परिस्थितियों में किसान जीवन यापन करते हैं जिनकी पीड़ा आज देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समझी है, जिसको देखते हुए उन्होंने देश के हजारों गरीब लोगों व गरीब किसानों के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम.किसान) योजना का लाभ प्रत्येक गरीब किसानो को मिले क्योकि सरकार की मंशा 2022 तक प्रत्येक किसान की आय दोगुनी करने की है। विधायक द्वारा जनपद स्तर पर कृशि के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने पर प्रकाश चंद पचौली, आशीष अग्रवाल ग्राम नगला तराई को उद्यान के क्षेत्र में, उमेद सिंह पोखरियाल ग्राम चक्करपुर विकास खण्ड खटीमा को पशु पालन के क्षेत्र में, त्रिलोक सिंह ग्राम भगवंतपुर विकास खण्ड जसपुर को मत्स्य पालन के क्षेत्र में 25.25 हजार के कृषि पुरस्कार चेक देकर कृषकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, प्रभारी जिलाधिकारी ने सभी किसानों का स्वागत करते हुए किसानों को समूह बनाकर अपने द्वारा उत्पादित फसलों को स्वयं विक्रय करने व मण्डी में रजिस्ट्रेशन करने की बात कही। ताकि बिचैलियों से बचा जा सके व किसानों को अपनी फसल का वास्तविक मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अर्न्तगत जनपद में अब तक 32363 किसानों को प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर पंजीकृत कर दिये गये हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि जो किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं वं किसान भी अपने निकट तहसील में जाकर अपना फार्म भरकर इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कृषक को प्रति वर्ष छह हजार रुपये के रूप में दी जाएगी जिसकी पहली किस्त गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुभारम्भ करने के बाद दो हजार की प्रथम किस्त के रूप में देश के लाखों किसानों के खातों में पहुंच जाएगी। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी-प्रभारी जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी जगदीश चन्द्र काण्डपाल द्वारा विभिन्न कृषकों को 10-10 हजार रुपये के कृषक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अपर जिलाधिकारी ने कृषकों को इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हुये कहा कि फार्म भरते समय अपना खाता संख्या सही अंकन करें ताकि लाभार्थियों को योजना की धनराशि मिल सके। उन्होंने कृषकों से इस योजना की जानकारी अन्य कृषकों को देने की भी बात कही। इसके अलावा मुख्य कृषि अधिकारी अभय कुमार सक्सेना ने कृषकों को भारत सरकार व राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर कृषक गोपाल सिंह, बिषन सिंह, हरि शंकर किच्छा, जगजीत सिंह चैती गांव, जसवंत सिंह कल्याणपुरी आदि उपस्थित थे

किसानों की आय दोगुनी करना प्राथमिकता : अजय

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दी जानकारी

अल्मोड़ा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं किसान मेले का शुभारम्भ विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में केन्द्रीय कपड़ा राज्यमंत्री अजय टम्टा द्वारा किया गया। इस अवसर पर राज्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय दोगुनी करने में सहायता मिलेगी साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे किसानों को इस योजना के प्रारम्भ होने से आर्थिक सहयोगा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ लोकसभा में लगभग 2.67 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। इस योजना में दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान आच्छादित होंगे जिन्हें प्रतिवर्ष छह हजार रुपये तीन किश्तों में जो 2000 रुपये प्रति किश्त के हिसाब से दिया जायेगा। इस धनराशि से छोटे एवं मझोले किसान खेती हेतु खाद, बीज व कीटनाशक आदि खरीद पायेंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही पहली किश्त डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में आनलाइन डाल दी जायेगी। इस कार्यक्रम के अवसर पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि जनपद में इस योजना से लाभान्वित किसानों की संख्या 97748 है। जिसमें 60204 किसानो ने आवेदन किया गया है और 23149 किसानों की सूचना पोर्टल पर आनलाइन अपलोड कर दी गयी है। इसके अलावा वर्तमान में पोर्टल पर अपलोड का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। जनपद में इस योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों का आनलाइन डाटा तैयार किया जा रहा है जिसकी मानिटरिंग दैनिक रूप से की जा रही है। उन्होंने बताया कि जल्दी ही सभी किसानो का डाटा आनलाइन तैयार कर उन्हें इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा। मुख्य कृषि अधिकारी, नोडल अधिकारी किसान सम्मान निधि योजना प्रियंका सिंह ने उपस्थित किसानों को इस योजना के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया साथ इस इस योजना का उद्देश्य, पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में बताया।

इस अवसर पर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डा. ए पटनायक ने संस्थान के क्रिया-कलापों एवं नवीन तकनीको के बारे में भी बताया। इस अवसर पर केन्द्रीय कपड़ा राज्यमंत्री ने किसान अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनेक पात्र किसानों को विवेक सोलर ड्रायर, खाद, बीज एवं कृषि यन्त्र वितरित किये। इससे पूर्व उन्होंने परिसर में विवेकानन्द कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा लगाये गये कृषि स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी मनुज गोयल, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ललित लटवाल, नगर अध्यक्ष कैलाश गूरूरानी, रमेश बहुगुणा, उपजिलाधिकारी विवेक राय, परियोजना निदेशक नरेश कुमार, खण्ड विकास अधिकारी हवालबाग पंकज काण्डपाल, डा. लक्ष्मीकान्त, अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष सीएल टम्टा, धमेन्द्र बिष्ट, दीपक पाण्डे, तुषारकान्त शाह सहित अनेक किसान एवं अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इससे पूर्व उपस्थित लोगों एवं किसानों द्वारा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का भी सजीव प्रसार देखा।

स्वीप टोल फ्री नम्बर 1950 का करें अधिकाधिक प्रचार

रुद्रपुर। आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने व सभी पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचन नामावलियों में अंकित करने के उद्देश्य से कलक्ट्रेट सभागार में बैठक मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश देते हुये कहा कालेजों व विद्यालयों में जो कैम्पस एम्बेसडर बनाये गये हैं साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सहायक नोडल अधिकारी (स्वीप) टोल फ्री नम्बर-1950 का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें ताकि मतदाता निर्वाचन से सम्बन्धित जानकारियां प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि स्वीप गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये नुक्कड़ नाटकों आदि से प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के साथ जिनके नाम निर्वाचन नामावली में नहीं जुड़े हैं वह भी अपना नाम जोड़ सकें। उन्होंने कहा कि जो बीएलओ अपने क्षेत्र में लापरवाही से कार्य करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि कैम्पस एम्बेसडर व सहायक नोडल अधिकारी स्वीप क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये जो भी कार्य कर रहे हैं उसे व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। बैठक में जीएम डीआईसी चंचल बोहरा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पीबी बुधलाकोटी, राजेन्द्र पाल, आरपी जोशी, डा. यूसी जोशी, वीके नेगी, डा. नरेन्द्र कुमार, खण्ड शिक्षा अधिकारी सहित विद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित थे।

कोसी पुनर्जनन अभियान को मिला प्रथम स्थान

अल्मोड़ा। केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल वाटर अवार्ड-2018 के लिये जनपद अल्मोड़ा के "कोसी पुर्नजनन अभियान" को प्रथम स्थान के लिये चुना गया है।

मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक कोसी पुनर्जनन अभियान को नदियों के संरक्षण-संवर्धन के लिए किये गए प्रयासों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला (उत्तर जोन) हेतु प्रथम स्थान के लिये चुना गया है। केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बीते दिनों नई दिल्ली में नेशनल वाटर अवार्ड-2018 दिया गया जिसमें आयुक्त कुमाऊँ मण्डल राजीव रौतेला, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, पूर्व मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित एवं एनआरडीएमएस के निदेशक प्रो. जेएस रावत, वन क्षेत्राधिकारी संचिता वर्मा ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

धार्मिक पर्यटन को दे रहे बढ़ावा : चौहान

अल्मोड़ा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों के प्रमुख मन्दिरों में पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। यह बात विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने प्रसिद्ध न्यायकारी देवता चितई गोलू मंदिर के समीप पार्किंग स्थल के शुभारम्भ करने पर कही। कहा कि जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने इस कार्य को मूर्तरूप देने के लिए विशेष रूचि दिखाई जिसके परिणाम स्वरूप इस कार्य को प्रारम्भ किया जा सका। उन्होंने बताया कि इस कार्य का निर्माण विधायक निधि से कराया जा रहा है। इस कार्य के प्रारम्भ हो जाने से देश व विदेश से आने वाले पर्यटकों को वाहन पार्किंग की सुविधा मिलेगी।

संपादकीय...

वनवासियों का हित

सुप्रीम कोर्ट ने करीब 12 लाख वनवासियों को राहत देते हुए उन्हें बेदखल करने के अपने ही आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट की एक बेंच ने 13 फरवरी को 16 राज्यों के करीब 11.8 लाख वनवासियों के वन–भूमि पर कब्जे के दावों को खारिज करते हुए राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि वे जमीनें खाली कराएं। अब इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने अदालत से उसके पिछले आदेश पर रोक लगाने की गुजारिश की थी। सरकार की दलील थी कि वनवासियों के अधिकार से संबंधित कानून को ठीक से न समझ पाने के कारण ही लाखों गरीब लोगों पर बेदखली का खतरा पैदा हो गया है। विडंबना देखिए कि जो कानून जंगलों में लंबे समय से रह रहे आदिवासियों और गैर आदिवासियों के हित में बना है, वही उनके लिए आफत साबित होने लगा। इसका कारण कानून की कुछ अपनी विसंगतियां भी हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि स्थानीय प्रशासन ने वनवासियों के प्रति संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। आज जब अनेक सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ तीखे तेवर अख्तियार किए हैं तो सरकार को भी आनन–फानन में वनवासियों के पक्ष में खड़ा होना पड़ा। ज्यादा बड़ी समस्या आदिवासियों के साथ नहीं, जंगल में रहने वाले गैर आदिवासियों के साथ है। यूपीए सरकार ने 'शिड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स (रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स) एक्ट 2008' के जरिए वन क्षेत्र में सदियों से रहने वाली जनजातियों और गैर जनजातियों का जंगल पर अधिकार सुनिश्चित करते हुए उनकी जीविका के लिए जरूरी प्रावधान किए। इसके तहत 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व वन भूमि पर काबिज अनुसूचित जनजाति के सभी समुदायों को वनों में रहने और आजीविका का अधिकार दिया गया लेकिन दूसरी ओर कानून की धारा 2 (ण) के अनुसार अन्य परंपरागत वन निवासियों के लिए तीन पीढ़ियों (एक पीढ़ी के लिए 25 साल) से वहां रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया।

प्रमाण पेश करने के लिए जो प्रक्रिया बताई गई, वह इतनी जटिल है कि कई समुदाय ऐसा दावा ही नहीं कर पा रहे। यदि झाबुआ में भील अनुसूचित जनजाति है तो उसे वन भूमि पर अधिकार मिलेगा, पर वही भील यदि किसी जिले में हो, जहां वह अनुसूचित नहीं है, तो उसे अन्य परंपरागत वन निवासी के रूप में दावा पेश करना पड़ेगा। कई लोगों को तो इस कानून की कोई जानकारी ही नहीं है। ज्यादातर के लिए सरकारी कागजात जुटाना लोहे के चने चबाने जैसा है। इन्हें बेदखली से बचाना जरूरी है क्योंकि एक मानवीय सवाल होने के अलावा पर्यावरण की रक्षा भी इससे जुड़ी है। कारण यह कि जंगलों के परंपरागत निवासी ही उनकी रक्षा करने में समर्थ हैं। इसके लिए कानून में भी समुचित बदलाव किए जाने चाहिए।

पहचान की लड़ाई

देश अभी पुलवामा अटैक के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि अरुणाचल प्रदेश में हिंसा की आग फैल गई। राज्य के मूल निवासी उन 6 समुदायों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र (पीआरसी) दिए जाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, जो मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश के निवासी नहीं माने जाते। गौरतलब है कि राज्य की बीजेपी सरकार देओरी, सोनोवाल कछारी, मोरान, आदिवासी और मिशिंग समुदायों को अरुणाचल प्रदेश में स्थायी निवास प्रमाण पत्र (पीआरसी) देना चाहती है। असम में अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाए ये समुदाय मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश के निवासी नहीं हैं, लेकिन दशकों से यहां के नामसाई और चांगलांग जिलों में रह रहे हैं।संयुक्त उच्चाधिकार समिति ने इस मामले में सभी पक्षों से बात करने के बाद इन्हें स्थानीय निवास प्रमाण पत्र देने की सिफारिश की है। यह प्रमाणपत्र मिल जाने के बाद इन समुदायों के लोग राज्य के मूल निवासी मान लिए जाएंगे और इसका लाभ उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और अचल संपत्ति खरीदने में मिलेगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी ऐसा मानते हैं कि इन लोगों को उन्हीं के ठीक बराबर का दर्जा देने से बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऐक्ट 1873 का उल्लंघन होगा, जिसके तहत राज्य में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के अनुसार सभी अस्थायी निवासियों और यात्रियों को राज्य में प्रवेश करने से पहले एक परमिट लेना पड़ता है। अब अगर गैर–निवासियों को पीआरसी दिया गया तो राज्य में ऐसे लोगों का आना बढ़ जाएगा, जिससे न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति पर बुरा असर पड़ेगा, बल्कि यहां के मूल निवासी जल्द ही अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे।

बहरहाल, अभी के हिंसक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पीआरसी बिल वापस ले लिया और कहा कि आगे भी उनकी सरकार यह मुद्दा नहीं उठाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए उनके इस आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकरण से पूर्वोत्तर में बीजेपी के सियासी अभियान को धक्का लगा है। उसकी योजना असम में नागरिकता (संशोधन) विधेयक और अरुणाचल में पीआरसी के बल पर अपना जनाधार बढ़ाने की थी। असम में वह बांग्लादेशी हिंदुओं और अरुणाचल में गैर–जनजातीय लोगों के रूप में अपना वोटबैंक देख रही थी। लेकिन फिलहाल ये दोनों ही उपाय उसे नुकसान पहुंचाते जान पड़ते हैं। यह सही है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी ने पूर्वोत्तर के राज्यों पर काफी ध्यान दिया है। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं और यहां के सारे राज्यों में बीजेपी कहीं सीधे तो कहीं सहयोगी के रूप में सरकार चला रही है। लेकिन इस इलाके की सामाजिक–सांस्कृतिक संवेदनशीलता के आकलन में उससे कुछ भूलें भी हुई हैं। राजनीतिक लाभ के लिए यहां की किसी भी सामुदायिक पहचान के साथ खिलवाड़ करना कई स्तरों पर घातक हो सकता है।

कश्मीर के नौजवान

जम्मू–कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इसे एक स्थानीय नौजवान ने अंजाम दिया। सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला करने वाला जैश–ए–मोहम्मद का आतंकवादी आदिल अहमद डार पुलवामा के काकापोरा गांव का रहने वाला था। एक साल पहले वह ग्यारहवीं में था। इससे उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस घटना ने 2000 में हुए बादामी बाग अटैक की याद ताजा कर दी, जब एक 17 साल के फिदायीन हमलावर ने विस्फोटकों से भरी मारुति 800 कार आर्मी कैंप में घुसा कर उसे उड़ा दिया। उसके एक साल बाद स्थानीय आतंकियों द्वारा जम्मू–कश्मीर विधानसभा के परिसर के बाहर किए गए एक कार बम विस्फोट में 38 लोग मारे गए थे।

पिछले कुछ समय से आतंकी संगठनों ने स्थानीय कश्मीरी नौजवानों की भर्ती तेज कर दी है।

युद्ध पहला विकल्प नहीं होता लेकिन अंतिम उपाय जरूर होता है

पुलवामा की आतंकवादी घटना के बाद से जिस प्रकार के कदम हमारी सरकार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा रही है उससे ना सिर्फ देश में एक सकारात्मक माहौल उत्पन्न हुआ है बल्कि इन ठोस कदमों ने हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल को भी ऊंचा किया है। लेकिन यह खेद का विषय है कि सरकार के जिन प्रयासों का स्वागत पूरा देश कर रहा है उनका विरोध देश की सबसे पुरानी राजनैतिक पार्टी कांग्रेस समेत जम्मू कश्मीर के स्थानीय विपक्षी दल कर रहे हैं। काश कि ये समझ पाते कि इनका गैर जिम्मेदाराना और सरकार विरोधी आचरण देश विरोध की सीमा तक जा पहुंचा है क्योंकि अपने राजनैतिक हितों के चलते इन लोगों ने कश्मीर समस्या को और उलझाने का ही काम किया है।पाक परस्ती के चलते जो लोग यह कहते हैं कि युद्ध किसी समस्या का विकल्प नहीं होता उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि युद्ध किसी समस्या का पहला विकल्प नहीं होता लेकिन अंतिम उपाय और एकमात्र समाधान अवश्य होता है। श्रीकृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता का ज्ञान देकर महाभारत के युद्ध को धर्म सम्मत बताया था। और जो लोग यह कहते हैं कि 1947 से लेकर आजतक कश्मीर के कारण भारत और पाकिस्तान में कई युद्ध हो चुके हैं तो क्या हुआ? तो उनके लिए यह जानना आवश्यक है कि हर युद्ध में हमारी सैन्य विजय हुई लेकिन राजनैतिक हार। हर युद्ध में हम अपनी सैन्य क्षमता के बल पर किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने के करीब होते थे लेकिन हमारे राजनैतिक नेतृत्व हमें किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं पाए। यह वाकई में शर्म की बात है कि हर बार हमारी सेनाओं द्वारा पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त देने के बावजूद हमारी सरकारें कश्मीर समस्या का हल नहीं निकाल पाईं। हर बार दुश्मन से सैन्य मोर्चे पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद भी हम राजनैतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर विफल रहे, 1948 में जब हमारी सेनाएँ पाक फौज को लगातार पीछे खदेड़ने में कामयाब होती जा रही थीं तो कश्मीर मामले को संयुक्तराष्ट्र क्यों ले जाया गया ? क्यों 1965 में हमें भारतीय सेना द्वारा पाक का जीता हुआ भू भाग वापस करना पड़ा। 1971 में जब पाक ने अपनी पराजय स्वीकार करी थी और भारतीय सेना के समक्ष 90000 हजार पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था तब संपूर्ण कश्मीर लेकर उसका स्थाई समाधान ना करके शिमला समझौता क्यों किया गया ?कारण जो भी रहा हो लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि हमारे द्वारा इतिहास में की गईं कुछ गलतियों की सजा पूरा देश आजतक भुगत रहा है खासतौर पर हमारी सेनाएँ और उनके परिवार। पहले जो पाकिस्तान आमने सामने से युद्ध करता था, अब आतंकवादियों के सहारे छिप कर वार करता है। लेकिन इस बार भारत का नेतृत्व इस मुद्दे पर आरपार की निर्णायक लड़ाई के लिए अपनी इच्छा शक्ति जता चुका है जिसका स्वागत पूरे देश ने किया। लेकिन इसे क्या कहा जाए कि आज जब देश की हर जुबाँ पर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की बात है तो महबूबा पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करती हैं। जब घाटी में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है तो वो विरोध करती हैं। 35। और 370 की बात आती है तो विरोध करती हैं। दरअसल इस प्रकार के नेता और उनके राजनैतिक स्वार्थ ही कश्मीर की समस्या के मूल में हैं। जब हमारे सैनिक इनकी रक्षा में शहीद होते हैं तब ये लोग आतंकवादियों से हथियार छोड़ कर बात करने के लिए क्यों नहीं कहते इसके विपरीत जब हमारी सेना कार्यवाही करने लगती है तो ये बातचीत से मुद्दे का हल निकालने की बात करते हैं। जब हमारी सेनाओं पर पत्थरबाजी होती है तो इन्हें पत्थरबाज भटके हुए बच्चे लगते हैं लेकिन जब अपने बचाव में इन पत्थरबाजों पर सेना कोई भी कार्यवाही करती है तो वो इन्हें सेना का अत्याचार दिखाई देता है।आखिर क्यों हमारे निहत्ते सैनिकों पर हमला करने वाले अब्दुल डार में इन्हें एक आतंकवादी नहीं एक भटका हुआ कश्मीरी दिखाई देता है। भले ही घाटी से पंडितों को खदेड़ दिया गया हो और विरोध में इन्होंने एक शब्द ना बोला हो क्योंकि कश्मीर पर सिर्फ कुछ विशेष कौमों का अधिकार है लेकिन इनका पूरे देश पर अधिकार है। इनका अधिकार है कि भारत सरकार इनकी सुरक्षा करे लेकिन ये भारत की सुरक्षा में कोई योगदान नहीं देंगे। इनका अधिकार है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आए तो भारत सरकार इनकी मदद करे लेकिन जब भारत पर आपदा आए तो इनका कोई दायित्व नहीं। यह इनका अधिकार है कि भारत सरकार जम्मू–कश्मीर के पृथक संविधान और ध्वज का सम्मान करे लेकिन भारत के संविधान और ध्वज का अपमान कश्मीर में हो सकता है। यह इनका अधिकार है कि भारत सरकार कश्मीर की संप्रभुता की रक्षा करे लेकिन भारत की संप्रभुता से इन्हें कोई लेना देना नहीं। यह इनका अधिकार है कि एक कश्मीरी भारत में कहीं भी रह सकता है भारत सरकार उसकी सुरक्षा करे लेकिन पूरे देश की सुरक्षा करने वाले सैनिक खुद भी कश्मीर में सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि इनका मानना है कि इनकी सुरक्षा में सुरक्षा बलों का शहीद हो जाना उनका फर्ज है और भारत सरकार से अपने लिए सहायता और सुरक्षा लेना इनका अधिकार है। लेकिन जिस सरकार से ये अपने लिए अधिकार मांगते हैं क्या उसके प्रति इनका कोई दायित्व नहीं है ? जिस सेना से ये बलिदान मांगते हैं क्या उनके प्रति इनके कोई फर्ज नहीं है ? इसलिए जरूरत है समय की नजाकत को समझा जाए। देशविरोधियों के चेहरों पर से नकाब हटाए जाएं।अगर 370 और 35। संविधान से हटाना नामुमकिन है तो संविधान में संशोधन करके एक और धारा जोड़ना तो मुमकिन है ? तो एक नई धारा जोड़ी जाए कि हर भारतीय की तरह कश्मीर के लिए भी भारत के संविधान, ध्वज, सेना और संप्रभुता का सम्मान और रक्षा सर्वोपरि होगी और भारत की अखंडता के खिलाफ किसी प्रकार की गतिविधि दंडनीय अपराध होगी। चूंकि कश्मीर भारत का ही अंग है इसलिए कश्मीर का ध्वज अकेले नहीं हमेशा भारत के ध्वज के साथ ही फहराया जाएगा।

-डा. नीलम महेंद्र

जवानों की खातिर

पिछले हफ्ते पुलवामा में हुए आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में सरकार का यह फैसला खासा अहम है कि कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों के जवान अब दिल्ली–श्रीनगर, श्रीनगर–दिल्ली, जम्मू–श्रीनगर और श्रीनगर–जम्मू आने–जाने के लिए हवाई सफर कर सकेंगे। पुलवामा में पिछले गुरुवार को सड़क मार्ग से गुजर रहे सीआरपीएफ के काफिले पर जैशे मोहम्मद के एक फिदायीन आतंकी हमले के चलते 40 जवानों के शहीद होने के गम से देश अभी उबर नहीं पाया है। हमले के बाद यह भी कहा गया कि सीआरपीएफ ने जवानों के लिए हवाई यात्रा की इजाजत मांगी थी, लेकिन वह संभव नहीं हो पाया। यह भी कि अगर जवानों को हवाई सफर की सुविधा मिल गई होती तो देश को इतना बड़ा सदमा नहीं झेलना पड़ता। गृह मंत्रालय ने हालांकि इजाजत मांगने संबंधी खबरों का खंडन किया, लेकिन यह सच है कि अर्धसैनिक बलों के जवान सामान्य स्थितियों में हवाई सफर के लिए अधिकृत नहीं थे। फिलहाल एक साल के लिए की गई इस व्यवस्था के मुताबिक केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों के जवान छुट्टियों पर ही नहीं, ड्यूटी पर भी आने–जाने के लिए इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस फैसले से न केवल अर्धसैनिक बलों, बल्कि पूरे देश में यह संदेश जाएगा कि सरकार के लिए अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा का सवाल भी सेना की सुरक्षा जितना ही अहम है। इस लिहाज से यह एक जरूरी फैसला है। मगर, जिन हालात में जवानों का कश्मीर में सड़क मार्ग से जाना इतना असुरक्षित हो गया है, उन्हें जल्दी बदलने की जिम्मेदारी भी इन जवानों पर ही है। जम्मू–कश्मीर में सक्रिय आतंकी शक्तियों में यह संदेश हरगिज नहीं जाना चाहिए कि वे भारतीय सुरक्षा बलों को सड़क से हटाने में सफल हो गए हैं। हां, हवाई सफर की सुविधा जवानों की ऊर्जा और उनका समय बचाती है, लिहाजा इसे आगे भी जारी रखा जाए और उनकी शक्ति का उपयोग लोकल दबिश बढ़ाने में किया जाए। ध्यान रहे, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को घाटी में बेहद कठिन लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यह वैसी लड़ाई नहीं है जिसमें दुश्मन की पहचान तय होती है। सीमा के अंदर चलने वाली इस लड़ाई में उन्हें बेकसूर नागरिकों की भीड़ में छुपे दुश्मनों का सामना करना है। ऐसे में सरकार तो अपना काम करेगी ही, देश के सामान्य नागरिकों की भी यह जिम्मेदारी है कि कश्मीर के आम लोगों पर गुस्सा जताकर वहां सुरक्षा बलों के काम को और मुश्किल न बनाएं। आम कश्मीरी इस देश के बाकी भू–भाग से जितना अपनापन महसूस करेगा, आतंकी तत्वों को अलग–थलग करके उन पर अंकुश लगाने में उतनी ही आसानी होगी। सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाना और उनके साथ डट कर खड़े रहना अभी जितना जरूरी है।

एक और सर्जिकल स्ट्राइक के साथ ही समान नागरिक संहिता भी लागू करिये

पत्रकारिता में आम धारणा है, शजब तोप मुकाबिल हो तो एक अखबार निकालो।श आशय यह कि शब्दों–विचारों की मारक क्षमता कतिपय शस्त्रों से अधिक होती है। विशेष तौर से सर्वव्यापी भी। यही वजह है कि जब पाकिस्तान की नापाक हरकतों के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग बलवती है तो मेरे मन में यह खयाल आया कि जम्मू–कश्मीर के उरी आतंकी हमले के बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक का फलाफल क्या निकला। जाहिर है, अंतराल दर अंतराल के इंतजार के बाद पुलवामा आत्मघाती आतंकी हमला हो गया। सवाल है कि यह सिलसिला आखिर कब और कैसे थमेगा? क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना से साफ कह दिया है कि इस घटना का बदला कब, कहां और कैसे लेना है, अपने पेशेवर रुख से वह खुद तय करे। प्रथमदृष्टया यह बहुत बड़ी बात है।लेकिन भारतीय शासन व्यवस्था की गतिविधियों को बड़े ही करीब से देखने के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस बार भी पाकिस्तान पर सर्जिकल हमला हो, ताकि उसे कड़ा सबक मिले।

लेकिन, इसके साथ ही श्भारतीय संविधानश से जुड़े उन तमाम प्रावधानों पर भी बौद्धिक–नीतिगत सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, जिससे ऐसे तत्वों को कानूनी खाद–पानी मिलती आई है। क्योंकि दुनियावी संविधान की श्वैचारिक खिचड़ीश समझे जाने वाले भारतीय संविधान के कुछेक प्रावधानों से भी ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ता है। साथ ही, देश में रणनीतिक विरोधाभास भी बढ़ता है। बानगी स्वरूप श्अल्पसंख्यकश शब्द की अवधारणा को ही ले लीजिए। यह कौन नहीं जानता कि साम्प्रदायिक विभाजन के परिणाम स्वरूप बने हिंद.ओं के हिन्दुस्तान और मुस्लिमों के पाकिस्तान में कथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो अगर–मगर करने की कोशिश की गई है, वह समाजशास्त्र की मूल प्रकृति के विपरीत है। शायद यही वजह है कि भारत आज उसकी भारी कीमत चुकाने की दिशा की ओर अग्रसर है। कारण कि जिन वजहों से 1947 में पाकिस्तान अलग हुए था, आज वही वजहें फिर से मुंह बाए खड़ी हैं। स्वाभाविक है कि दोष परिस्थितियों का कम, उन नीति–नियंताओं का अधिक है जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय लोकप्रियता हासिल करने के लिए हिंदुओं के दूरगामी हित से एक नहीं, बल्कि कई नापाक समझौते किये, जिनका यहां उल्लेख करना मैं जरूरी नहीं समझता हूं, क्योंकि ये सभी बातें पब्लिक डोमेन में हैं।

सवाल है कि अल्पसंख्यक वर्ग के नाम पर भारत में मुस्लिमों या अन्य धर्मावलम्बियों को जो अतिरिक्त सुविधाएं दिए जा रही हैं, उसका औचित्य क्या है ? और सिर्फ धर्म ही क्यों, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग आदि के नाम पर जो तरह तरह के वाद स्थापित किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं, वह क्या राष्ट्रीयता के लिहाज से उचित हैं ? किसी भी लो.कतंत्र में वोट बैंक के लिहाज से यदि नैसर्गिक व सार्वभौमिक मानवीय, सामाजिक और प्रशासनिक मूल्यों से छेड़छाड़ की जाएगी, तो नीतिगत विरोधाभास बढ़ेंगे ही। भारत इसी अव्यवहारिक अंतर्द्वंद्व से गुजर रहा है। इसलिए सत्ताधारी वर्ग समान नागरिक संहिता का समर्थक होते हुए भी लाचार दिख रहा है। इसलिए खंडित–विखंडित लाभों पर फिर से विचार करने की जरूरत है, जो कि एक लंबे अरसे से महसूस की जा रही है।सबसे बड़ा नीतिगत सवाल यह है कि आखिर फिरंगियों की सोच पर उधार लिए हुए कतिपय कानूनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस नए भारत का निर्माण करेंगे, यह जानने का हक हिंदुस्तानियों को है। देश ही नहीं दुनिया को भी है, क्योंकि एनआरआई पूरे देश में फैले हुए हैं। फिर भी यदि हमारी संसद और सुप्रीम कोर्ट विगत 70 सालों में भी आस्तीन के सांपों की तरह काम करने वाले कानूनी शब्दों या प्रावधानों की पहचान नहीं कर पाई है तो यह उसका श्बौद्धिक दिवा.लियापनश है, जिससे राष्ट्रवाद, एकता और अखंडता की अवधारणा निरंतर खोखली होती जा रही है। इससे देश में विघटनकारी तत्वों को प्रश्रय मिल रहा है और शेष देशवासी अपने ही वीर जवानों की लाशें यत्र तत्र सर्वत्र गिनने को अभिशप्त हो चुके हैं।

क्या आपने कभी सोचा है कि फूट डालो और राज करो जैसी हिंसक नीति से जब अंग्रेजों की सत्ता चिरस्थाई नहीं हो पाई, तो श्काले अंग्रेजोंश की कितनी होगी, समझना आसान है! और बिगड़ते हालात दिन ब दिन इस बात की चुगली भी कर रहे हैं। गुलामी की पीड़ा यदि भुला भी दी जाए तो आजादी के साथ ही विरासत में मिले हुए साम्प्रदायिक दंगों, फिर 1948 में महात्मा गांधी की हत्या, 1962 के चीनी आक्रमण, 1965 के भारत–पाक युद्ध से उपजी ताश.कंद त्रासदी, 1971–72 का भारत–पाक युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण, 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल, 1980 के दशक का खालिस्तानी आतंकवाद और 1984 का इंदिरा हत्याकांड, एलटीटीई आतंकवाद और 1991 का राजीव हत्याकांड, कारगिल युद्ध 1999, मुम्बई आतंकी हमला 2008, उरी आतंकी अटैक 2016 और अब पुलवामा आतंकी आत्मघाती हमला 2018 से जो सिलसिलेवार सख्त संदेश मिले हैं, और वक्त–वेवक्त जो साम्प्रदायिक झड़पें होती रहती हैं, उसकी भयावह आंच यत्र–तत्र आम लोगों पर पड़ते–पड़ते अब हमारे वीर जवानों तक पहुंच चुकी है। जिसका मुंहतोड़ जवाब शस्त्रों से अधिक मारक प्रभाव रखने वाले शब्दों से देने की जरूरत है, अन्यथा मुकाबला मुश्किल है।सवाल फिर वही कि जब आम आदमी और खास आदमी के वोट की कीमत समान है तो फिर अन्य कानूनी विसंगतियां और नीतिगत–रणनीतिक लापरवाहियां आखिर किसके हितवर्द्धन के लिए बनाये रखी गई हैं, यह जानने को देशवासी उत्सुक हैं। बेशक अल्पसंख्यकवाद के समतुल्य ही जातिवादी आरक्षण व्यवस्था की अवधारणा से भी देश खोखला होता जा रहा है।

क्योंकि इसके आर्थिक स्वरूप का तो स्वागत किया जा सकता है जिससे वर्गवाद पनपेगा, लेकिन जातीय स्वरूप का कतई नहीं, क्योंकि इससे सामाजिक विखंडन पैदा होगा, हो भी रहा है। खास बात यह कि किसी भी तरह के आरक्षण पर पहला हक तो गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत के अमर शहीदों के परि.जनों का होना चाहिए, लेकिन इस दिशा में कदम उठाने की बात शायद किसी ने भी नहीं सोची तो क्यों, समझना मुश्किल नहीं है?

बेशक, देश और समाज आज विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है। सरकारी व्यवस्था का विकल्प बन रही निजीकरण व्यवस्था का यत्र–तत्र आर्थिक नंगा नाच सिर चढ़कर बोल रहा है जिससे राष्ट्रवादी भावना को वह मजबूती नहीं मिल पा रही है जिसकी अपेक्षा देशवासियों को है। या फिर जैसी चीनियों और पाकिस्तानियों में आमतौर पर देखी–पाई जा रही है।सवाल फिर वही कि आखिर जिस निकृष्ट लो.कतांत्रिक प्रवृति को प्रश्रय देकर यह देश खोखला होता जा रहा है, उसकी प्रासंगिकता और समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप उसमें आवश्यक बदलाव लाने के बारे में आखिर सोचेगा कौन ? क्योंकि अब यह महसूस किया जाने लगा है कि ऐसे अपेक्षित बदलाव लाने में हमारी संसद व विधानमंडल और क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय विफल या फिर असहाय प्रतीत हो रहे हैं, जो सार्वजनिक चिंता का विषय है। लिहाजा, समकालीन प्रबुद्ध वर्ग का यह नैतिक दायित्व है कि वह देश को एक नई और सर्वस्वीकार्य दिशा दिखाए, जिसकी अपेक्षा और जरूरत समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समर्थ भारत के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा है। खासकर एनजीओ की अवधारणा का सदुपयोग इस दिशा में किया जाए तो बेहतर रहेगा।

लेकिन इसके लिए सत्ता, शासन, न्यायिक, मीडिया और कारोबारी शीर्ष पर बैठे और उनसे जुड़े लोगों और विशेषकर छोटे–छोटे सामाजिक धड़ों के संगठित पहरेदारों को आम आदमी के दूरगामी और बुनियादी हितों के प्रति उदार होना होगा। क्योंकि पुरातन अथवा समकालीन दौर में बढ़ती भोग की प्रवृति और इसकी पूर्ति हेतु हर ओर मची मार–काट से इतर श्सनातन भारतश के सेवा और त्याग की उदात्त सोच को अपनाना होगा, अन्यथा स्थिति बहुत जटिल से जटिलतम बन चुकी है।

शायद अब खतरा इस बात का है कि आतंकवाद के रथ पर सवार इस्लामिक दुनिया जब हिंदुत्व के प्रतीक समझे जाने वाले भारत को निगलने को तत्पर प्रतीत हो रही हो और आहिस्ता–आहिस्ता आगे बढ़ रही हो, तब मुकाबले के सिवाय अन्य चारा भी बचा है क्या ? उधर, ईसाइयत व्यवस्था भी इस ताक में बैठी है कि दिन प्रतिदिन बेतुके धर्म–संघर्ष में उलझते जा रहे भारत को कैसे अपना सहज ग्रास बनाया जाए और फिर से उसे अपना आर्थिक गुलाम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की आड़ लेकर बनाया जाये, क्योंकि उसका आर्थिक हित इसी में सुरक्षित है।

सवाल है कि क्या आप इन बातों को सोच पा रहे हैं और इस देश के आम आदमी को समझा पा रहे हैं। यदि नहीं तो अब भी सोचिए, समझिए और अंदर से हिल चुके देश को एक नई मजबूती देने के लिए आगे आकर समर्थ नेतृत्व दीजिये। वैसा उदारमना नेतृत्व विकसित कीजिए जो दलित, पिछड़ी, अल्पसंख्यक, भाषाई, क्षेत्रीयता, लिंग भेद, साम्प्रदायिकता, जातीयता, परिवारवाद और सम्पर्कवाद जैसी संक्रामक वैचारिक बीमारियों और उससे उपजी निकृष्ट सोच से परे हो। जो समान मताधिकार की तरह समान नागरिक संहिता यानी कि अन्यान्य असमानताओं को दूर करने की पैरोकारी करता हो। जो भारत को भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने वाली अटल–आडवाणी युगीन बीजेपी की अवधारणा–विचारधारा के विराट रूप का दर्शन जन–जन को आत्म–साक्षात्कार के माध्यम से करवाने में समर्थ हो। अन्यथा देश का वैचारिक दलदल इस सद्भावी राष्ट्र को भी ले डूबेगा, पूर्णतया समाप्त कर देगा, जिससे पूरी मानवता संकट में पड़ जाएगी, आज नहीं तो निश्चय कल!

-कमलेश पांडे

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आलेख में व्यक्त विचार उनके अपने हैं।

प्राधिकरण सचिवों की कार्यशैली से कमिश्नर नाराज

आयुक्त ने बैठक में दिये आवश्यक दिशा निर्देश

हल्द्वानी। जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक गुरूवार को आयुक्त–अध्यक्ष प्राधिकरण श्री राजीव रौतेला की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। ज्ञातव्य है कि मण्डल मे 06 विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं। बोर्ड की बैठक में विभिन्न जनपदों को प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर आयुक्त रौतेला द्वारा स्वीकृतियां जारी की गई। इस बैठक में सभी जिलाधिकारी मौजूद थे। रौतेला ने कहा कि अधिकारियों को प्राधिकरण की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि लोगों को प्राधिकरण के कार्यो की जानकारी हो सके और लोग प्राधिकरण की सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि मण्डल में कार्यरत सभी प्राधिकरण जनआकांक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। मानचित्र स्वीकृत करने की गति काफी धीमी होने के कारण लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। प्राधिकरण में तकनीकी स्टाफ तथा अवर अभियन्ताओं की कमी होने के कारण भी ऐसा हो रहा है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अन्य विभागों से कार्यरत अवर अभियन्ताओं को प्राधिकरण मे सम्बद्ध करते हुये उन्हे प्राधिकरण के कार्यो एवं गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि अवर अभियन्ता अपने–अपने विभागीय कार्यो के साथ ही प्राधिकरण से सम्बन्धित मानचित्र परीक्षण स्वीकृत कार्य तथा प्रबन्धन कार्य को भी सम्पन्न कर सकें। आयुक्त रौतेला ने अपर आयुक्त संजय खेतवाल को सभी प्राधिकरणों कार्यालयों की समीक्षा एवं अनुश्रवण का नोडल नामित किया है। उन्होने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि वे अपने स्तर पर माह मे एक बार प्राधिकरण के कार्यो की समीक्षा अवश्य करें। बैठक मे यह तथ्य भी सामने आया कि मण्डल के किसी भी प्राधिकरण द्वारा जनउपयोगी प्राधिकरण की वेबसाइट नहीं बनाई गयी है और ना ही उसकी लांचिग की गई है। उन्होंने प्राधिकरण के सभी सचिवों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि छह माह से पहले दिये गये आदेशों के बाद भी वेबसाइट ना बनना गम्भीर है। उन्होने सभी सचिवों को आदेशित किया कि वह अपने–अपने प्राधिकरण की डायनामिक वेबसाइट बनाना सुनिश्चित करें तथा उसमे सभी सूचनाओं को हिन्दी और इंगलिश भाषा मे अपलोड करें। उन्होने प्राधिकरणों मे सात दिनो के भीतर कार्मिकों की नियुक्ति के प्रस्ताव शासन को भेजने के भी निर्देश दिये। आयुक्त ने जिलाधिकारी डा. नीरज खैरवाल को एक सप्ताह के भीतर रूद्रपुर प्राधिकरण भवन एवं सर्किट हाउस रुद्रपुर हेतु भूमि के प्रस्ताव देने के भी निर्देश दिये। बैठक में जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन, रंजना राजगुरु, नितिन भदौरिया, डा.विजय कुमार जोगदण्डे, डा.रणवीर सिंह चौहान, मुख्य वन संरक्षक डा. पराग मधुकर धकाते, अपर जिलाधिकारी आरडी पालीवाल, टीएस मर्तोलिया, कैलाश टोलिया, राहुल भटनागर, सचिव प्राधिकरण हरवीर सिह,जयभारत सिह, केवल खुराना, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक एसके पंत,एसएम श्रीवास्तव सहा नियंत्रक कुमाऊं, मुख्य कोषाधिकारी अनिता आर्या, सिटी मजिस्टेट पंकज उपाध्याय, उपजिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल के अलावा मण्डलीय अधिकारी उपस्थित थे।

प्रियंका गांधी के आते ही कांग्रेस को मिलने लगे हैं नये गठबंधन

कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रियंका वाड्रा प्रदेश कांग्रेस का श्संदेशश लेकर दिल्ली चली गई हैं। दिल्ली में इस पर अलग से मंथन होगा। संदेश साफ है कि कांग्रेस को किसी भी दल से सीटों की श्खैरातश नहीं मांगनी चाहिए। इससे जनता में गलत मैसेज जाता है और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। वैसे भी २०१७ के विधान सभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने का हश्र देखा जा चुका है। मात्र सात सीटों पर सिमट गई हैं कांग्रेस। कांग्रेसियों को तो अभी भी यही लगता है कि अगर २०१७ में अकेले चुनाव लड़ा जाता तो हम कम से कम ५० सीटों पर जरूर जीत हासिल कर लेते। हुआ इसका उलट। अखिलेश सरकार के खिलाफ चल रही सत्ता विरोधी लहर में कांग्रेस भी तिनके की तरह उड़ गई। इसका मतलब यह नहीं है कि सपा के साथ जाने से हुए नुकसान के बाद कांग्रेस ने गठबंधन की सियासत से ही तौबा कर ली है। गठबंधन तो होगा, लेकिन उन दलों से जो कांग्रेस के वर्चस्व और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सहज स्वीकार करेंगे। जब ऐसे दलों की बात होती है तो इसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर महान दल, शिवपाल यादव की नवगठित श्प्रगतिशील समाजवादी पार्टीश, राजा भैया की जनसत्ता पार्टी, भाजपा से छिटकती दिख रही चार विधायकों वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल भी कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। बसपा.सपा के साथ अभी तक खड़ा नजर आ रहा राष्ट्रीय लोकदल भी ज्यादा सीटें मिलने की दशा में कांग्रेस की तरफ आ सकता है। इसकी वजह है प्रियंका वाड्रा के आने के बाद कांग्रेस की स्थिति में सुधार आना। कांग्रेस जिन छोटे दलों को साथ लेकर चलना चाह रही है उनका भले ही पूरे यूपी में प्रभाव न हो, लेकिन सीमित क्षेत्र में इनकी मतदाताओं पर अच्छी खासी पकड़ है।यह दल कांग्रेस के साथ आने के लिए इसलिए इच्छुक भी हैं क्योंकि चंद दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रियंका वाड्रा एक नया श्सितारा श बन कर आई हैं। उनसे कांग्रेस को उम्मीदें हैं तो विपक्ष को खतरा। माया.अखिलेश की तो पूरी रणनीति पर ही ग्रहण लग गया है। इसी के चलते सपा.बसपा अपने प्रत्याशियों की नई लिस्ट बना रही हैं ताकि प्रियंका फैक्टर से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। यह और बात है कि प्रियंका के नाम पर अभी जनता बंटी हुई है। किसी को प्रियंका में इंदिरा दिखती हैं तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो इंदिरा गांधी से प्रियंका की तुलना को गैर.जरूरी मानते हैं।खैर, इन बातों से बेफिक्र प्रियंका कांग्रेस का कायाकल्प करने के लिए श्मैराथन दौड़श लगा रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का आगमन प्रदेश कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। यह बात प्रियंका की श्शख्सियतश, श्काबलियतश और हाजिर जवाबी ने साफ कर दी है। अब तो चारों तरफ यही चर्चा है कि राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका पर दाँव लगाकर कुछ गलत नहीं किया। इसकी कुछ बानगी देखिए। प्रियंका गांधी मीडिया से रूबरू नहीं हुई थी। मगर मीडिया कहां छोड़ने वाला था। ऐसे ही जब प्रियंका का मीडिया कर्मियों से आमना. सामना हुआ तो एक पत्रकार ने रहबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के संबंध में जब पूछा तो प्रियंका ने बड़ी हाजिर जवाबी दिखते हुए कहा, श्यह सब तो चलता ही रहेगा।श उनके इतना कहते ही रहबर्ट वाड्रा के नाम पर प्रियंका को घेरने की को. शिश करने वालों के मुंह पर ताला लग गया। इसी प्रकार जब प्रियंका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी साफगोई से कह दिया कि मोदी का मुकाबला करने के लिए राहुल हैं। यानी वह यह मैसेज नहीं देना चाहती थीं कि मोदी का हराने का जिम्मा उन्होंने राहुल से लेकर अपने कंधों पर डाल लिया है। अगर प्रियंका मान लेतीं कि हाँ वह मोदी से मुकाबला करेंगी तो विरोधी शोर मचाने लगते कि राहुल फेल हो गए हैं, इसलिये मोदी से मुकाबले को प्रियंका को आगे लाया गया है।प्रियंका के आते ही कांग्रेस को नए साथी भी मिलने लगे हैं। महान दल से गठबंधन हो गया है। शिवपाल यादव भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए प्रियंका के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। १४ फरवरी को प्रियंका की लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस थी, लेकिन उससे पहले कश्मीर में आतंकी हमला हो गया, जिसमें ४० आरपीएफ के जवान शहीद हो गए। प्रियंका ने सियासी समझदारी दिखाते हुए प्रेस कांफ्रेंस रद्द कर दी, उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि तो दी ही इसके साथ यह भी कह दिया कि वह शहीद होने वालों के परिवार का दर्द समझती हैं। प्रियंका का इशारा दादी इंदिरा और पिता राजीव गांधी की शाहादत की ओर था। प्रियंका ने प्रेस कांफ्रेंस नहीं की, लेकिन अपने अगल.बगल बैठे दो लोगों का परिचय मीडिया से जरूर करा दिया। यह नेता मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर से भाजपा विधायक अवतार सिंह भडाना और पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद रामलाल राही थे। इन दोनों नेताओं की प्रियंका ने घर वापसी कराई। प्रियंका का चार दिवसीय लखनऊ दौरा समाप्त चुका है, लेकिन इन चार दिनों में प्रियंका ने कांग्रेस को काफी कुछ दे दिया। कांग्रेसियों के हौसले बढ़े हुए हैं। लब्बोलुआब यह है कि प्रियंका कांग्रेस की सोई हुई आत्मा को जगाना चाहती हैं ताकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से पहले वाली मजबूत कांग्रेस का सपना साकार हो सके।

–अजय कुमार

शिक्षक बनते ही पढ़ना लिखना कम कर देंगे तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा

एक हाथ रिक्शा खींचने वाला किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है इसकी समझ इस तरह से बनाई जा सकती है कि वह अपना पेट पालने के लिए कर्ज लेकर या किराए पर ई–रिक्शा चलाने का कौशल सीख रहा है। ताकि घर.परिवार चला पाए। ठीक उसी तरह हर पेशे में समय समय पर नई तकनीक और व्यावसायिक दक्षता सीखने की आवश्यकता पड़ती है। यदि कोई व्यवसायी ऐसा नहीं करता तो वह अपने पेशे में पिछड़ जाता है। शिक्षण. प्रशिक्षण भी एक ऐसा पेशा है जो समय समय पर सीखे हुए कौशल को बारंबार मांजने की वकालत करता है। हकीकत है कि शिक्षक एक बार एनटीटी, बी.एड करने के बाद अपने औजारों को मांजना और धारदार बनाने के प्रति बहुत ज्यादा सचेत और सक्रिय नजर नहीं आता। इन तमाम वास्तविकताओं के बावजूद अभी भी ऐसे शिक्षक हैं जो लगातार विभिन्न सेमिनारों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं में जाकर अपनी शिक्षण समझ और ज्ञान को पुनर्नवा करते हैं। समस्त भारतवर्ष में वर्ष में दो बार अध्यापक शिक्षण.प्रशिक्षण कार्यशालाओं के मुख्य महाकंभ लगा करते हैं। इसे मई.जून और दिसंबर. जनवरी माह में लगने वाले महाकुंभ के नाम से पुकार सकते हैं। इस महाकुंभ में कई बार आदेशानुसार स्नानार्थी भाग लेते हैं तो कुछ स्वेच्छा से डुबकी लगाया करते हैं।

जो स्वेच्छा से आते हैं उन्हें कई बार खाली हाथ लौट जाना पड़ता है उन्हीं कक्षाओं में जहां उनकी कर्मस्थली है। अपनी ओर पूरी को. शिश करते हैं कि वे अपनी कक्षाओं में बदलाव घटा सकें।हमने कार्याशालायी शिक्षक.प्रशिक्षण कुंभ की बात की। इन कुंभों में जिस प्रकार से रिसोर्स पर्सन का चयन होता है, विषयों का बंटवारा किया जाता है उसे गहराई से समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि कई बार रिसोर्स पर्सन को एक दिन पूर्व संपर्क किया जाता है कि कल कार्यशाला है आपको सत्र लेना है। एक गंभीर रिसोर्स पर्सन पूछता है और पूछना ही चाहिए कि कल की कार्ययोजना क्या है? क्या उद्देश्य है आदि तो तब महसूस होता है कि किस लचर तरीके से इस महाकुंभ की तैयार की जाती है। दिलचस्प तो यह जानना भी है कि इस महाकुंभ में आने वाले प्रतिभागी आते.जाते, सोते.जगते, अंदर.बाहर करते वक्त्त काट दिया करते हैं। उन्हें भी पिछले कई सालों का अनुभव है कि वास्तव में समय 9. 30 का है लेकिन 10.30 या 11.00 बजे से पहले शुरू नहीं होगा। शुरू हो भी गया तो रिसोर्स पर्सन अपने निजी अनुभवों की पोटली खोल कर कुछ चूरन बांटेंगे। जिन्हें प्रसाद मिल रहा है वो भी और देने वाला भी जानता है कि इन चूरनों से कक्षा में पढ़ाना और सीखना.सिखाना नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी चूरन का वितरण होता है।पिछले दिनों एक राष्ट्रीय स्तर की दो दिवसीय कार्यशाला श्अध्यापक प्रशिक्षक अध्यापकीय व्यावसायिक दक्षता विकासश पर शिक्षा के विभिन्न सहयोगियों जिसमें शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक, एनजीओ, सीएसआर आदि शामिल थे। सबने एक से एक नायाब सुझाव और आंकड़ों के पहाड़ खड़े किए। आरोपों.प्रत्यारोपों के दौर से पूरी सभा सन्न थी। शिक्षक, प्राध्यापक सब के सब खामोश और खिन्न थे। सबकी नजर अंत में शिक्षक पर ही पड़ी। शिक्षक समुदाय बौखला उठे। उनका तर्क था कि सबसे पहले और प्रमुखता से शिक्षक पर सारी कमियों की गठरी डाल दी जाती है। सवाल यह है कि यदि शिक्षक शिक्षण के लिए है तो एसे पाठ्यपुस्तक के अति. रिक्त शिक्षा.साहित्य और रिपोर्ट आदि भी पढ़ने चाहिए ताकि उसकी समझ और ज्ञान अधुनातन रह सके। हालांकि यह सामान्यीकृत वक्तव्य के रूप में लेने की वजह से शिक्षक समुदाय बचाव के पक्ष में खड़ नजर आते हैं।वास्तविकता यह भी है कि अधिकांश शिक्षक एक बार सीखने. सिखाने के क्षेत्र में आ जाते हैं उसके बाद पढ़ना.लिखना लगभग कम हो जाता है। यही वे स्तर हैं जहां से शिक्षक फिसलने लगते हैं। हर व्यवसाय की अपनी कुछ मांगें होती हैं जिन्हें यदि जिम्मदारी से न निभाया तो व्यक्ति अपने कर्म व पेशे के साथ न्याय नहीं कर पाता। उक्त विमर्श में विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव रखने वाले लोग शामिल थे। उनमें प्रथम, क्राई, एनसीईआरटी और टेक महिन्द्रा फाउंडेशन थे। हर किसी ने अपने अपने खास क्षेत्र के अनुभव साझा किए। टेक महिन्द्रा फाउंडेशन के कौशलेंद्र प्रपन्न ने बताया कि सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण किस प्रकार सेवारत में तब्दील होता है तब किस प्रकार की दुश्वारियां सामने आती हैं। एक बार सेवापूर्व प्रशिक्षण लेकर आए शिक्षक ज्यादा लंबे समय तक कक्षायी चुनौतियों के सामने खड़े नहीं हो पाते। उन्हें बीच–बीच में अपनी औजार मांजने और धार चढ़ाने की आवश्यकता होती है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आदि के अंतर्गत वर्ष में दो बार कार्यशालाओं में शिक्षकों को बुलाया जाता है। इन कार्यशालाओं में आने वाले शिक्षक और रिसोर्स पर्सन आदि जिनका जिक्र ऊपर किया गया, बहुत अधिक लाभकारी नहीं मानते। क्योंकि जिस प्रकार से प्रशिक्षण कार्यशालाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है उसे कार्यान्वित कराने में कई स्तरों पर अड़चनें आती हैं। इन्हें बिना दूर किए हम सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के पहाड़ तो खड़े कर सकते हैं किन्तु गुणवत्तापूर्ण कार्यशाला की उम्मीद नहीं कर सकते। इस क्षेत्र में टेक महिन्द्रा फाउंडेशन पिछले छह वर्षों से पूर्वी दिल्ली नगर निगम में अंतःसेवाकालीन अध्यापकों के साथ प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है।केंद्रीय शिक्षा संस्थान, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित इस राष्ट्रीय गोष्ठी में देश के विभिन्न शिक्षा.शिक्षण संस्थानों के शिक्षक.प्रशिक्षक एवं शोधार्थी शामिल थे। इन पंक्तियों के लेखक ने साझा किया कि एक अच्छा शिक्षक.प्रशिक्षक कैसे और किन व्यावसायिक दक्षता के आधार पर श्रेष्ठ शिक्षक.प्रशिक्षक आदि बन सकता है। यदि हमारा शिक्षक. प्रशिक्षक कक्षायी व स्कूली परिवेश में बच्चों की गलतियों को स्वीकार करे और उसे गलती के तौर पर रेखांकित करने की बजाए सीखने.सिखाने की प्रक्रिया का प्रमुख हिस्सा के तौर पर स्वीकार करे। दूसरा, एक अच्छा शिक्षक यदि कक्षायी विविधताओं को अस्वीकार करने की बजाए उन्हें स्वीकार कर अपनी शिक्षक विधियों में उन्हें स्थान दे तो वह शिक्षक निश्चित ही श्रेष्ठ शिक्षक.प्रशिक्षक बन सकता है। तीसरी कड़ी है, बच्चों व अन्य अवलोकनकर्ताओं के सुझाव को कमियों के तौर पर न लेकर एक शुभेच्छा के तौर पर स्वीकार कर उन पर अभ्यास कर दूर कर सके तो वह शिक्षक.प्रशिक्षक श्रेष्ठता की ओर बढ़ सकता है। चौथा और प्रमुख अपने और बच्चों की गतिविधियों, कार्यों आदि की रणनीति एवं गति का मूल्यांकन करते हुए आगे और अगले दिन, माह की रणनीति तैयार करे।

बजट दबाएं नहीं, विकास कार्यो में खर्च करें : सुमन

हल्द्वानी। जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने सर्किट हाउस में जिले में चलाए जा रहे विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2018–19 अवसान की तरफ है, महज कुछ दिन ही इस वित्तीय वर्ष में बचे हैं। लिहाजा जिन विभागों को विकास कार्यों को अंजाम देने के लिए स्वीकृत हुई है उसका हर हाल में शतप्रतिशत उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि बहुत से अधिकारी बजट को दबाए रखते हैं और खर्च न कर पाने की दशा में सर्मित कर देते हैं, यह आचरण घोर आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब तबके के आर्थिक उन्नयन एवं विकास के लिए जो धनराशि प्राप्त हुई है, उसे यदि कोई अधिकारी समर्पित करेगा तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। लिहा. जा उपलब्ध धनराशि का शतप्रतिशत उपयोग जनहित में किया जाए।

जिले को जिला योजना के माध्यम से विकास कार्यों को अंजाम देने के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत परिव्यय के सापेक्षे 38 करोड़ 61 लाख की सकल धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त हो चुकी हैं जोकि सभी विभागों को आवंटित कर दी गयी है। ऐसे में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। यह बात जिलाधिकारी विना. द कुमार सुमन ने विकास कार्यों की प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र सभागार में समीक्षा करते हुए कही।उन्होंने जिला योजना के साथ ही राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित योजनाओं की प्रगति एवं व्यय की समीक्षा भी की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओ के अन्तर्गत धनराशि खर्च करते हुए जो कार्य किये जा रहे है, उन कार्यों पारदर्शिता व गुणवत्ता के साथ ही कार्यो का अनुश्रवण भी किया जाए।

सुमन ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद के विकास कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि किसी भी दशा में लेप्स नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 की घोषणा कभी भी की जा सकती है, लिहाजा इस वित्तीय वर्ष के जो भी नए कार्य शुरू करने हो वह तत्काल शुरू कर लिए जाए। उन्होंने जिला योजना में लोनिवि 2 किमी ग्रामीण सड़क निर्माण के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि 150 लाख के सापेक्ष 95 लाख की धनराशि व्यय करने (अवमुक्त धनराशि का 63 प्रतिशत व्यय करने), लोक निर्माण विभाग को अवमुक्त धनराशि 650 लाख की धनराशि के सापेक्ष 411 लाख की धनराशि का व्यय (अवमुक्त धनराशि का 63 प्रतिशत व्यय) करने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि वित्तीय वर्ष के अवशेष एक माह के भीतर धनराशि का शतप्रतिशत उपभोग करना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि जिला योजना के अन्तर्गत शासन से अवमुक्त 38.61 करोड़ रूपये की धनराशि के सापेक्ष 30.77 करोड़ की धनराशि व्यय हो चुकी है जोकि अवमुक्त धनराशि का 79.7 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि राज्य सैक्टर के अन्तर्गत शासन से अवमुक्त 254.00 करोड़ रूपये की धनराशि के सापेक्ष 204.4 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय हो चुकी है जोकि अवमुक्त धनराशि का 80 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि केन्द्र पोषित सैक्टर के अन्तर्गत शासन से अवमुक्त 183.65 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष 150.99 करोड़ की धनराशि व्यय हो चुकी है जोकि अवमुक्त धनराशि का 82 प्रतिशत है।

जिले के बेरोजगारों को दिलाएं स्वरोजगारपरक प्रशिक्षण : खैरवाल

जिलाधिकारी खैरवाल ने ली जिला स्तरीय समीक्षा समिति

रुद्रपुर। जिला स्तरीय समीक्षा समिति व जिला समन्वय समिति की बैठक मे जिलाधिकारी डा. नीरज खैरवाल द्वारा निर्देश देते हुए कहा कि बैंकर्स व विकास से जुड़े अधिकारी आपसी सामन्जस्य बनाते हुए कार्य करें ताकि जनपद के अधिक से अधिक पात्र लोगों को सरकारी योजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराकर योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पात्र लोगों को लाभान्वित करने के लिए जो आवेदन पत्र बैंकों में लम्बित हैं उनका शीघ्र निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जनपद के 87 बैंकों में आधार सेंटर खोले गये हैं। उन्होंने कहा कि जिन बैंकों में आधार सेंटर खोले गये हैं वे अपने बैंकों में आधार केन्द्रों के बैनर भी लगायें ताकि आमजन को इसकी जानकारी हो सके। जिलाधिकारी ने कहा एनआरएलएम (आजीविका) व स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सीसीएल एवं टर्म लोन देने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें ताकि महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार से जोड़ा जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में रोजगार से सम्बन्धित जो भी कार्य चलाये जा रहे हैं, उसका फायदा बेरा. जगार युवक–युवतियों को होना चाहिए ताकि वे प्रशिक्षण के बाद अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। उन्होंने निदेशक आरसेटी को निर्देश देते हुए कहा कि तीन वर्ष के अन्तर्गत जिन छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया है, उनकी वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में अवगत करायें। उन्होंने कहा कि आरसेटी के अन्तर्गत जनपद में वही प्रशिक्षण दिये जायें जिससे प्रशिक्षण ले रहे छात्र–छात्रा रोजगार से जुड़ सकें। जिलाधिकारी ने अग्रणी बैंक प्रबन्धक मधुसूदन सुमन को निर्देश देते हुए कहा कि आमजन को सुविधा देना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसलिए सरकारी योजनाओं के ऋण के लिए जो भी आवेदन पत्र बैंकों को भेजे जाते हैं इसके लिए एक साफ्टवेयर तैयार करें ताकि सभी सूचनाएं एक ही पोर्टल पर प्राप्त की जा सकें। किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा केसीसी का लक्ष्य 15 मार्च तक पूर्ण कर लिया जाए इसके लिए सभी बैंकर्स प्रयास करें। बैंक ऋण वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा इस कार्य में सभी बैंक प्रबन्धक रूचि लें। उन्होंने कहा कि बैंकर्स सम्बन्धित उप जिलाधिकारी व तहस. ीलदार के साथ बैठकर वसूली प्रमाण पत्रों का मिलान करें। ऋण वसूली में जिला प्रशासन बैंकों का पूर्ण सहयोग करेगा। बैठक में डिजिटल बैंकिग, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, स्वतः रोजगार योजना, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि की समीक्षा की गई।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मयूरी दीक्षित, अपर जिलाधिकारी उत्तम सिंह चौहान, पीडी हिमांशु जोशी, जीएम डीआईसी चंचल बोहरा, लीड बैंक अधिकारी मधुसूदन सुमन, नाबार्ड के विशाल शर्मा, आरबीआई के विशाल यादव, सहकारी बैंक के पीसी दुम्का, बीओबी के सुखदेव राज, एसबीआई के राजीव रावत सहित जनपद के बैंक अधिकारी उपस्थित थे।

भारत के सामने पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेल की धमकी बेअसर साबित हुई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरी हार्दिक बधाई कि उन्होंने हमारी फौज को वह करने दिया, जो उसे करना ही चाहिए था। पिछले डेढ़ हफ्ते में मैं चार बार लिख चुका हूं और कई टीवी चौनलों पर कह चुका हूं कि भारत को आतंकवादियों के अड्डों पर तत्काल हमला करना चाहिए था, चाहे वे लाहौर में हों, बहावलपुर में हों, पेशावर में हों, या काबुल में हों या कंधार में हो। यह हमला किसी देश पर नहीं, सिर्फ उसके आतंकी अड्डों पर है। हमारे विदेश सचिव ने क्या खूब शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि यह हमला 'गैर–फौजी' हमला है ?वास्तव में यह न तो किसी फौजी निशाने पर था और न ही यह नागरिकों के विरुद्ध था। इसका लक्ष्य और चरित्र अत्यंत सीमित था। यह सिर्फ आतंकियों के खिलाफ किया गया ठेठ तक पीछा (हॉट परस्यूट) था, जिसे अंतरराष्ट्रीय कानून भी मान्यता देता है। वास्तव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इसका मौन स्वागत करना चाहिए था, जैसे कि पाकिस्तान की फौज और सरकार ने ओसामा बिन लादेन की हत्या का किया था। लेकिन यह भारत है। अमेरिका नहीं। पाकिस्तान की जनता इमरान को कच्चा चबा डालती। अब इमरान और पाकिस्तान क्या करे ? परमाणु–शक्ति बनने के बाद यह पहली बार हुआ कि भारत ने आगे होकर कदम बढ़ाया है। दूसरे शब्दों में अब पाकिस्तानी परमाणु–ब्लैकमेल की धमकी भी बेअसर हो गई है। इसीलिए पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बहुत ही दिग्भ्रमित लग रही है।यदि विदेश मंत्री कहते हैं कि भारतीय विमान नियंत्रण–रेखा के अंदर बस 2–3 किमी तक आए थे और सिर्फ तीन मिनिट में ही वे डरकर वापस भाग गए तो मैं पूछता हूं कि आपको इतने बौखलाने की क्या जरूरत थी ? पाकिस्तान में आपकी सरकार के लिए शर्म–शर्म के नारे क्यों लग रहे हैं ? संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है ? अपने मनपसंद समय और स्थान पर हमले की बात क्यों कही जा रही है ? जब कुछ हुआ ही नहीं तो बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं ? जहां तक भारत का सवाल है, इस सीमित और संक्षिप्त हमले का असर भारत की जनता पर अत्यंत चमत्कारी हुआ है। सारे देश में उत्साह का संचार हो गया है। विरोधी दल भी सरकार की आवाज में आवाज मिलाने को तैयार हो गए हैं। सरकार ने जिन तीन आतंकी केंद्रों पर हमला करके 300 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है, उसके प्रमाण देना वह उचित समझे या न समझे लेकिन यह सत्य है कि उसके हमले से कश्मीर के अंदरूनी और बाहरी आतंकवादियों की हड्डियों में कंपकंपी दौड़ जाएगी। यदि सरकार मेरे उन सुझावों पर भी अमल करे, जो मैंने कश्मीर के अंदरूनी आतंकवाद से निपटने के लिए दिए हैं तो यह निश्चित है कि पाकिस्तान की आतंकवादी ताकतें अपने आप पस्त हो जाएंगी। यह मौका है जबकि इस्लामी सहयोग संगठन के सदस्यों से सुषमा स्वराज बात करें और उनसे कहें कि वे पाकिस्तान की सरकार, फौज और जनता से कहें कि इस मामले को तूल देकर युद्ध की शक्ल न दे दें।

–डा. वेदप्रताप वैदिक

चैलेंज के रूप में लें निर्वाचन ड्यूटी : खैरवाल

जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक

रुद्रपुर। लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 को जनपद में शान्ति एवं पारदर्शिता के साथ सफल सम्पादन के लिए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डा. नीरज खैरवाल की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार कक्ष में सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर व जोनल पुलिस ऑफिसरों की बैठक ली। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियों का पालन एक चैलेन्ज के रूप में लेने को कहा। उन्होने कहा प्रत्येक ऑफिसर व कर्मचारी को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत अपने–अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा तभी चुनाव को शान्ति व पारदर्शिता के साथ सम्पन्न किया जा सकता है।

उन्होंने अधिकारियों को दिये गये क्षेत्रों व पोलिंग बूथों का अभी से बारीकी से निरीक्षण कर ले ताकि कोई भी कमी को समय रहते दूर किया जा सकें। उन्होने कहा कि पोलिंग बूथ व पोलिंग एरिया में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिये जिसमें विद्युत, पानी दिव्यांगों के लिए पोलिंग बूथों पर रैंप, शौचालय भवन की स्थिति, दूर संचार व्यवस्था, रूट चार्ट आदि की व्यवस्था का सही–सही अंकन करें। साथ ही संवेदन व अति संवेदन स्थानों को भी चिन्हित करें ताकि समय पर उन स्थानों पर नजर रखा जाय। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को आरओ,एआरओ व सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट एवं जोनल, सेक्टर पुलिस ऑफिसर तथा चुनाव से जुड़े अन्य अधिकार व कर्मचारी आपस में समन्वय बनाकर रखें जिसके लिये उन्होंने व्हाटसप ग्रुप बनाने की भी बात कही ताकि चुनाव के दौरान कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसका शीघ्र ही सामाधान किया जा सकें। उन्होने अधिकारियों को ईवीएम व वीवीपैड की सही जानकारी के साथ ही मतगणना के बाद तक सुरक्षित रखने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी प्रलोभन व लालच या किसी भी दबाव में कार्य न करने को कहा।

इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिन्दरजीत सिंह, मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित,एडीएम उत्तम सिंह चौहान, मुख्य कोषाधिकारी भूपेन्द्र प्रसाद काण्डपाल, एसपी प्रमोद कुमार, एसडीएम नरेश चन्द्र दुर्गापाल सहित सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर जोनल पुलिस आफिसर उपस्थित थे ।

सरहद पे है तनाव और मुलुक में है चुनाव

मुलुक तो हमेशा ईच ऊप्पर है, पन अबी मुलुकपरस्ती सुपर डुपर है। अबी निकले ईच थे देख के फिलिम 'उरी' और वो भाई लोक पुलवामा में चला दिएले दिल पे छुरी बावा, अपुन लोक तो अपुन के गांधी बाबा के अमन अहिंसा के, बोले तो पीसफुल लोक हैं। भोत टाइम पे तो अपुन दूसरा गाल बी आगे कर देता है, पन कोई दिमाग की नस कू जास्ती ईच खींच देता है, तो अपुन के इदर का अनपड़ आदमी बी गीता पड़ने कू लगता है, क्या! तो अबी क्या है ना भाय, बोले तो इमोशनल बर्स्ट है, बोले तो इंडिया फर्स्ट है, बाकी सब वर्स्ट हैं। मुलुक तो हमेशा ईच सबका ऊप्पर है, पन अबी मुलुक परस्ती, बोले तो देशभक्ति सुपर डुपर है। क्या तो हो गया भाय, बोले तो अबी तो बोलना ईच शुरू किया था, बोले तो हाऊ इज द जोश! अबी निकले ईच थे देख के फिलिम 'उरी' और वो भाई लोक पुलवामा में चला दिएले दिल पे छुरी। तो फिर तो ये होने कू ईच था, बोले तो राम, राफेल और बेरोजगारी बन गएले रेजगारी। अबी तो बस, एक ईच बात थी, बदला। और अपुन की फोर्स ने लिया भाय बदला। एक बार फिर था उनका इलाका और अपुन का धमाका, बोले तो अलस्सुबे सुबे नींद में डूबे दहशत के अजूबे। क्या है ना, वो अपुन का नेबर, बोले तो भोत जबर है भाय। खुद के घर में ढेकूण, बोले तो खटमल और कीड़े– बांदे पालता है और इलम से अपुन के घर में डालता है और अपुन की लाइफ का अमन– चौन बिगाड़ता है। अपुन उसकू भोत टाइम बोला, 'बस क्या भाय, कबी तलक चलेंगी तेरी ये चिल्लमचिल्ली, पन वो मानने कू ईच नई होता और बोलने कू लगता है, 'कौन बोला? पएला सबूत दो, तबी अपुन कुच करेंगा।' भोत टाइम सबूत बी दिया, पन वो करने कू बी क्या सकता है, बोले तो मुजरिम खुद कू सजा सुनाएंगा क्यातो ये टाइम अपुन खुद ईच उसकी खोली में घुस के सिरिप पेस्ट कंट्रोल किया भाय, बस और बता दिया, बोले तो अब देख ले सबूत।

स्थों के दायरे

सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा ऐसे समय हुई, जब पूरा देश पुलवामा अटैक को लेकर शोकाकुल है। संयोग से युवराज पहले पाकिस्तान गए थे लेकिन भारत की आपत्ति का ध्यान रखते हुए वह सीधे पाकिस्तान से भारत नहीं आए बल्कि अपने देश जाकर वापस इस तरफ लौटे।

इससे एक बात तो जाहिर है कि उन्हें भारत की भावनाओं का ध्यान है। दिल्ली के अपने वक्तव्य में प्रिंस मोहम्मद ने सीधे–सीधे पुलवामा हमले की निंदा तो नहीं की, पर कहा कि चरमपंथ और आतंकवाद पर भारत और सऊदी अरब की चिंताएं समान हैं। यह भी कि इससे लड़ाई में वह खुफिया सूचना साझा करने सहित सभी तरीकों से भारत का सहयोग करेंगे। इस मौके पर दोनों देशों के बीच पांच समझौतों पर हस्ताक्षर हुए जिनमें 'नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड' में निवेश तथा पर्यटन और आवास के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। इसके साथ ही भारत के इन्वेस्ट इंडिया और सऊदी अरब के जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के बीच द्विपक्षीय निवेश संबंधों के लिए और प्रसार भारती तथा सऊदी ब्रॉडकास्ट कोऑपरेशन के बीच मिलकर कार्य करने के लिए हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह प्रोटोकॉल तोड़कर शहजादे का स्वागत किया, उससे स्पष्ट है कि भारत सऊदी अरब को कितनी तवज्जो देता है। लाखों भारतीय वहां रोजी–रोजगार के लिए गए हुए हैं। 2016 में वहां भारतीयों की संख्या बढ़कर करीब 30 लाख पहुंच गई थी। 2014–15 में दोनों देशों के बीच 39.4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जबकि पाकिस्तान और सऊदी के बीच व्यापार 6.1 अरब डॉलर का ही था।

सम्पादक : विनोद चन्द्र पनेरू

स्वामी प्रकाशक, मुद्रक तथा सम्पादक **विनोद चन्द्र पनेरू** द्वारा भीड़ापानी–ओखलकाण्डा, प्रिंटिंग प्रेस, भोलानाथ गार्डन, हल्द्वानी (नैनीताल) से मुद्रित तथा तल्ली बमौरी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड से प्रकाशित। प्रकाशित खबरों के लिए प्रेस उत्तरदायी नहीं है। मो.- 9410354318 E-mail:- vinodpaneru123@gmail.com

फागुन उत्सव में बहे लोक संस्कृति के रंग

हर्षोल्लास के साथ मनाया गया एमबीपीजी कालेज का वार्षिकोत्सव

हल्द्वानी। एमबीपीजी डिग्री कॉलेज के वार्षिकोत्सव एवं फागुन उत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉ.स्वराज विद्वान तथा मेयर जोगेन्द्र पाल सिंह रौतेला ने दीप जलाकर किया। उत्सव में दो मिनट का मौन रखकर पुलवामा आतंकी हमले तथा अन्य घटनाओं में प्राणों की आहूती देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

एनसीसी के विद्यार्थियों द्वारा देश भक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमो के माध्यम से माहौल को देश भक्तिमय बना दिया। डॉ.स्वराज ने उत्सव में विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उत्सव के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा किताबी ज्ञान के अतिरिक्त अर्जित किये गए व्यावहारिक ज्ञान, देश की संस्कृति, कला एवं परम्पराओं के अर्जित ज्ञान एवं हुनर को दिखाने का अवसर मिलता है। उन्होंने महाविद्यालय द्वारा सामाजिक क्षेत्र में एनएसएस, एनसीसी व रक्तदान के माध्यम से किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए आगे भी सामाजिक क्षेत्र में और अधिक कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से अनुशासित रहते हुए शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उत्साहित किया।

उन्होंने कहा कि देश में युवा शक्ति 65 प्रतिशत से भी अधिक है। देश को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रत्येक क्षेत्र में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में युवा शक्ति के प्रवेश ने आन्दोलन को द्रुत गति प्रदान की और देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने युवा शक्ति को शक्तिबल का एहसास कराते हुए समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में आगें आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश वासियों में देश भक्ति प्राचीन काल से विद्यमान है तथा आवश्यकता पड़ने पर कोई भी व्यक्ति देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहूती देने में कोई संकोच नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि देश प्राचीन काल से वीरो एवं वीरांगनाओं देश है। देश के दुश्मनों को समझ लेना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर कोई भी देशवासी देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा एवं ज्ञान के अभाव में देश का चहुमुँखी विकास असंभव है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारे सैनिक सीमाओं पर अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार देश के विकास के लिए विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी अपनी जिम्मेदारियॉ समझते हुए शिक्षा का दीपक प्रत्येक घर में जलाना होगा तथा कोई भी नागरिक शिक्षा से वंचित न रहे।

लोक गायक गजेन्द्र राणा ने जय हो नन्दा देवी तेरी जय हो के माध्यम से राज्य की संस्कृति एवं परमपराओं से रूबरू कराया। इसके साथ ही उनकी बब्ली तेरू मोबाईल, लाली हो सिया, फूर्की बांद आदि अन्तरा वाले गीतों के माध्यम से विद्यार्थियों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। लोक गायिका माया उपाध्याय की मनमोहक प्रस्तुतियों हाय ककड़ी झिल मां, ओ मेरी चन्दा ने तथा गायक किशन सिंह हरियाला की रानीखेत की हिमुली, राकेश खनवाल के पहाड़ो ठण्डो पानी, बसंती छोरी ने दर्शकों को भाव–विभोर कर दिया।

महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वन्दना तथा स्वागत गीत प्रस्तुत किया तथारूमल का गांठा, डीडीहाट की विमला छौरी, नीमा छौरिये आदि पहाड़ी गीतो पर प्रस्तुत नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। व्यायाम प्रशिक्षुओं द्वारा योग नृत्य के माध्यम से सभी नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित किया। क्षेत्र की उभरती हुई प्रतिभा राहुल यादव ने अभिनेता नाना पाटेकर, इरफान खान, अमरेश पुरी, शाहरूख खान, अजय देवगन की मिमीक्री के माध्यम से सबको आश्चर्यचकित करने के साथ ही हॅसने पर मजबूर कर दिया।

इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य जीएस बिष्ट ने महाविद्यालय का वार्षिक प्रगति एवं आख्या रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर महाविद्यालय की मेधावी विद्यार्थियों मनीषा सुयाल तथा आस्था नेगी के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।इस अवसर पर मण्डी समिति के अध्यक्ष गजराज बिष्ट तथा प्रदीप बिष्ट व मेयर जोगेन्द्र पाल सिंह रौतेला ने भी अपने–अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का संचालन डॉ.विनय शंकर विद्यालंकर द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में छात्र संघ अध्यक्ष गौरव कोरंगा, उपाध्यक्ष सौरभ कुमार आर्य, छात्रा उपाध्यक्ष शोभा जोशी, सचिव गौरव सनवाल, उप सचिव रवि यादव, कोषाध्यक्ष हिमांशु जोशी, सांस्कृतिक सचिव सागर अधिकारी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि कृति तिवारी के अलावा प्रोफेसर बीएस रावत, अजय राजौर, अरूण राही, समीर आर्य, अरुण राही, मनोज जोशी, सुन्दर आर्य सहित विद्यार्थी एवं महाविद्यालय का स्टॉफ उपस्थित था।

अल्मोड़ा में रोजगार मेले में उमड़ी बेरोजगारों की फौज

चयन के बाद 508 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र

अल्मोड़ा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन राजकीय इण्टर कालेज अल्मोड़ा में किया गया। मेले का शुभारम्भ केन्द्रीय कपड़ा राज्यमंत्री अजय टम्टा एवं विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने किया इस मेले में राज्य के सिडकुल पंतनगर, हरिद्वार, देहरादून, सितारगंज एवं स्थानीय स्तर पर स्थापित विभिन्न औद्योगिक इकाईयों जिनमें मुख्य रूप से अशोक लिलेण्ड, रायल इण्डिया, श्रीराम जनरल इंशोरेंस, वोन इण्डिया, आदित्य इन्टरप्राइजेज, केलीबर बिज़नेस सर्पोट, स्टार मेनेजबकमेंट, आई0सी0आई0सी0 बैंक के अलावा जिला उद्योग केन्द्र, आरसेटी, होटल एसोशिएसन, सेवायोजन विभाग सहित 34 कम्पनियों ने प्रतिभाग किया।

इस रोजगार मेले में लगभग 1500 सौ अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया जिनमें 1010 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया। विभिन्न कम्पनियों द्वारा 508 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र,शार्टलिस्ट किया गया। मुख्य अतिथि केन्द्रीय कपड़ा राज्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत सरकार के कौशल भारत सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने हेतु यह रोजगार मेला स्थानीय बेराजगारो को रोजगार के नये अवसर मुहैया कराने हेतु एक मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के अन्तर्गत बेरोजगार अभ्यर्थी अपने हुनर को पहचान कर विभिन्न कम्पनियों में अपनी सेवायें प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस मेले में पंजीकृत अभ्यर्थियों को मेले का अधिकाधिक लाभ उठाकर रोजगार प्राप्त करना चाहिए। इ स अवसर पर विशिष्ट अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान में रोजगार एक बड़ी आवश्यकता है रोजगार से किसी भी प्रदेश एवं जिले की विकास दर तय की जाती है इस तरह के रोजगार मेलो के आयोजन से युवाओं को अपने स्वरोजगार में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जल्दी ही एक और वृहद मेला आयोजित कराने का प्रयास किया जायेगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के स्टैट हैड जयकान्त सिंह ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में रोजगार मेले का आयोजन कर विभिन्न कम्पनियों एवं नियोजकों को आमंत्रित कर स्थानीय बेराजगारो को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगो को अधिकाधिक इस रोजगार मेले का लाभ लेना चाहिए। उन्होंने विभिन्न कम्पनियों एवं नियोजको का आभार व्यक्त किया। मेले में स्वरोजगार के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 05 लोगो को कौशल सारथी पुरस्कार प्रदान किये गये जिसमें मोहन सिंह खोलिया, महेश आर्या, गीता रावत, नवीन कुमार, निशा रानी को स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी मनुज गोयल, उपजिलाधिकारी विवेक राय, उद्यमिता मंत्रालय के सुधांशु जोशी, मोहम्मद कलीम, समीर सिंह, सेवायोजन अधिकारी एएस बिष्ट, ललित मोहन मेहता, धमेन्द्र बिष्ट सहित विभिन्न कम्पनियों के नियोजक एवं अनेक अभ्यर्थी उपस्थित थे। संचालन चन्द्र प्रकाश फुलेरिया ने किया।

डीआईसी हल्द्वानी के प्रबंधक पांडे सेवानिवृत्त

हल्द्वानी। 35 साल और तीन माह का राजकीय कार्यकाल पूरा कर जिला उद्योग केंद्र में तैनात प्रबंधक योगेश चंद्र पांडे सेवानिवृत्त हो गए हैं। सेवा. निवृत्ति पर सहकर्मियों ने उन्हें स्मृति चिह्न भेंट कर विदाई दी और कार्यकाल की सराहना की। गुरुवार को जिला उद्योग केंद्र में प्रबंधक योगेश चंद्र पांडे का विदाई समारोह आयोजित किया गया। मूलरूप से अल्मोड़ा के रहने वाले पांडे ने विभाग में एक दिसंबर 1983 को सेवा शुरू की थी। इसके बाद वे कुमाऊं के तमाम स्थानों पर तैनात रहे। उधमसिंहनगर में जिला महाप्रबंधक रहने के दौरान भी उन्होंने विभागीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार के साथ ही बेरोजगारों को लाभांवित करने के लिए काफी प्रयास किये। इधर हल्द्वानी में तैनाती के दौरान भी कई मेला–प्रदर्शनियों व विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कुशलता पूर्वक संचालन व संपादन किया। विदाई के दौरान जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विपिन कुमार ने स्मृति चिह्न भेंट कर उनके उज्जवल, स्वस्थ्य व दीर्घायु जीवन की कामना की। इस मौके उधमसिंहनगर डीआईसी के प्रबंधक सुनील कुमार पंत सहित तमाम विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

बाल विभाग को अवशेष धनराशि खर्च करने के आदेश

हल्द्वानी। जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जिले को नन्दा–गौरा योजना के अन्तर्गत पांच करोड़ 93 लाख की धनराशि शासन से आवंटित हुई है। इस योजना के अन्तर्गत नवजात बच्चियों तथा कक्षा 8वी, 10वी, 12वी उत्तीर्ण छात्राओं को आर्थिक मदद दी जाती है। उन्होंने बताया कि आवंटित धनराशि में से चार करोड़ 88 लाख 27 हजार की धनराशि खर्च की जा चुकी है। जिससे जिले की 8832 बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि इस समय योजना के अन्तर्गत एक करोड़ 5 लाख की धनराशि अवशेष पड़ी है। उन्होंने इस बात पर हैरानी और नारा. जगी व्यक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुलेखा बिष्ट को निर्देशित किया कि वह अनिवार्य रूप से 31 मार्च तक इस धनराशि का उपभोग सुनिश्चित करें। उन्होंने जनपद की पात्र बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों से अपील की है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने आवेदन विलम्बतम 5 मार्च तक मुख्य शिक्षा अधिकारी (शिक्षित बालिकाओं के लिए तथा नवजात बालिकाओं के आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी अथवा जिला कार्यक्रम अधिकारी विकास भवन में जमा करा दें।